हिन्दी दैनिक

पथ प्रवाह

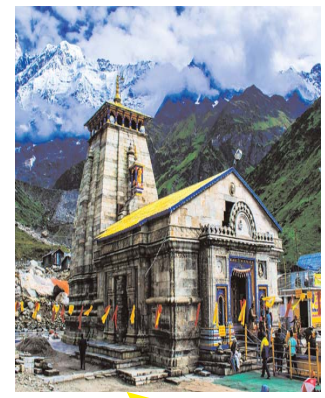

RNI No.: UTTHIN/2011/39282

निर्भीक, निष्पक्ष, सच का प्रवाह

वर्ष:5 अंक:151 पृष्ठ:08 मुल्य:1 रूपये | pathpravah.com | हरिद्वार, रविवार, 07 जून 2026

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने 'खेत बचाओ अभियान' को बताया जनांदोलन, 6 करोड़ की तारबाड़ योजना

पथ प्रवाह, अल्मोड़ा

जलवायु परिवर्तन के बीच कृषि को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से हवालबाग में राज्य स्तरीय 'खेत बचाओ अभियान' का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 'खेत बचाओ अभियान' अब सरकारी कार्यक्रम नहीं, जनभागीदारी से जुड़ा जनांदोलन बन चुका है। उन्होंने किसानों से मिट्टी, कृषि भूमि और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। सीएम ने कहा कि किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि देश की शक्ति और हिम्मत हैं। मिट्टी मां के समान पूजनीय है, इसलिए खेतों को रासायनिक पदार्थों से मुक्त रखना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा जनपद में तारबाड़ योजना के तहत करीब 6 करोड़ रुपये की लागत से कार्य कराने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए बजट में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। किसान हित में पॉलीहाउस, फलोत्पादन, कोल्ड स्टोरेज, मेगा फूड पार्क और सुगंधित फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 23 हजार हेक्टेयर में सुगंधित फसलों का उत्पादन हो रहा है।

सीएम ने नियमित मिट्टी परीक्षण, पानी का विवेकपूर्ण उपयोग और वैज्ञानिक शोध के अनुरूप खेती करने का आह्वान किया। मांडुआ, झंगोरा, चौलाई समेत मोटे अनाजों के संरक्षण व उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन जरूरी है। डीबीटी से योजनाओं का लाभ सीधे किसानों को मिल रहा है, बिचौलिए खत्म हुए हैं।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि खेत बचाकर ही आत्मनिर्भर उत्तराखंड संभव है। ड्रैगन फ्रूट, कीवी व मिलेट को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया गया।

इस मौके पर विधायक डॉ. प्रमोद नैनवाल, मोहन सिंह मेहरा, महेश जीना, जिला पंचायत अध्यक्ष हेमा गैडा, मेयर अजय वर्मा, कृषि सचिव सुरेंद्र नारायण पांडे, सीडीओ रामजी शरण शर्मा समेत जनप्रतिनिधि, अधिकारी व बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।

एक नजर

प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई प्राथमिकी नहीं : दिल्ली पुलिस

नयी दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने यहां जंतर मंतर इलाके में हुए प्रदर्शन को लेकर शनिवार शाम स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी है। दिल्ली पुलिस को यह बयान इसलिए जारी करना पड़ा क्योंकि कुछ सोशल मीडिया साइटस और पोस्ट में यह दावा किया गया था कि पुलिस ने वहां पहुंचे आंदोलनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल ऐसी खबरें और दावे पूरी तरह भ्रामक हैं। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपुष्ट और भ्रामक जानकारी पर भरोसा न करें और न ही उसे आगे साझा करें।

ईरान ने कहा, ट्रंप के साथ किसी भी परमाणु समझौते पर भरोसा नहीं, अमेरिका से रुक गयी है बातचीत

तेहरान। ईरान के सर्वोच्च नेता के एक वरिष्ठ सलाहकार एवं इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) के पूर्व कमांडर-इन-चीफ मोहसिन रेजाई ने वर्ष 2015 के जेसीपीओए समझौते से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीछे हटने का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका के साथ फिलहाल परमाणु पर कोई बातचीत नहीं होगी। रेजई ने यह भी कहा कि ईरान-अमेरिका के बीच बातचीत बंद हो गयी है और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए श्री ट्रंप को कदम उठाना चाहिए। ईरानी मीडिया के अनुसार, आईआरजीसी के पूर्व प्रमुख ने अमेरिका को दोबारा आक्रामकता दिखाने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा, 'अगर उन्होंने फिर से सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुना, तो वह एक अंधेरी और अंतहीन सुरंग में प्रवेश कर जायेंगे। उन्होंने कहा कि अगर युद्ध और नाकेबंदी जारी रही तो ईरान इस टकराव को फारस की खाड़ी से आगे हिंद महासागर, लाल सागर, बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य और भूमध्य सागर तक बढ़ा सकता है। रेजाई ने इस बात पर जोर दिया कि बातचीत गतिरोध पर पहुंच गयी है और ईरान के फ्रीज किये गये फंड को जारी करना विश्वास बहाली के लिए एक जरूरी परीक्षा है। उन्होंने 'सीएनएन' से कहा, ' अब गेंद ट्रंप के पाले में है और ईरान के रोके गये फंड को जारी करना विश्वास बहाली के उपाय के रूप में काम करेगा। यह बातचीत आगे बढ़ाने के अमेरिका की ख्वाहिश का इम्तिहान भी होगा। '

सरकार ने जारी की दायित्वधारियों की तीसरी सूची

पथ प्रवाह, देहरादून।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने दायित्वधारियों की तीसरी सूची जारी करते हुए 6 नेताओं को विभिन्न आयोगों, बोर्डों और सलाहकार समितियों में उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है। नई नियुक्तियों में ओमवीर सिंह राघव, धीरेंद्र पंवार, भूपेंद्र कंडारी, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल रघुवीर सिंह भंडारी, रणजीत सिंह नामधारी और किरन शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन नियुक्तियों से विभागीय योजनाओं की निगरानी मजबूत होगी, जबकि राजनीतिक विश्लेषक इसे आगामी विधानसभा चुनावों से पहले संगठनात्मक और सामाजिक संतुलन साधने की रणनीति मान रहे हैं। पिछले तीन दिनों में जारी सूचियों के साथ दायित्वधारियों की संख्या 100 के पार पहुंच चुकी है।

चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड सैलाब, 55 दिनों में 31 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन

नई दिल्ली। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा इस वर्ष नए रिकॉर्ड बना रही है। यात्रा शुरू होने के महज 55 दिनों के भीतर 31 लाख से अधिक श्रद्धालु बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं। श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार और प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और यातायात व्यवस्थाओं को और मजबूत किया है।

चारधाम यात्रा के तहत सबसे अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ केदारनाथ और बदरीनाथ धाम में देखने को मिल रही है। यात्रा सीजन की शुरुआत से ही देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। सरकार का दावा है कि दर्शन, आवागमन, पार्किंग और आवास की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया गया है, जिससे यात्रियों को काफी सुविधा मिल रही है। मानसून के आगमन को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को यात्रा मार्ग पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए होल्डिंग एरिया, भोजन, स्वास्थ्य सेवाओं और पार्किंग की अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है। हालांकि यात्रा के दौरान स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी सामने आई हैं। रिपोर्टों के अनुसार यात्रा के पहले महीने में विभिन्न कारणों से कई श्रद्धालुओं की मौत हुई, जिसके बाद स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा सुविधाओं को और सुदृढ़ किया गया है। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है और आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

धर्मनगरी में चौथे दिन भी अतिक्रमण के खिलाफ गरजा बुलडोजर, ध्वस्त किये गए अवैध कब्जे

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

सरकारी भूमि, सड़क, नालियों एवं फुटपाथ पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ धर्मनगरी में चौथे दिन भी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान पक्के अतिक्रमणों को जेसीबी की सहायता से ध्वस्त किया गया। इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्का फुल्का विरोध भी हुआ लेकिन पुलिस फोर्स की मौजूदगी में यह अभियान जारी रहा।

जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों, नगर निगम एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी सरकारी भूमि,सड़क, फुटपाथ एवं नालियों के ऊपर अतिक्रमण न हो,जो भी अतिक्रमण किया गया है, उससे हटाने के निर्देश दिए गए है। जिलाधिकारी ने वर्तमान में चल रही चार धाम यात्रा एवं आगामी कांवड़ मेले को सुव्यवस्थित एवं सुगम संचालित करने के लिए एव यात्रियों को आवागमन में कोई परेशानी एवं असुविधा न हो तथा जनपद में जाम की स्थित न हो इसके दृष्टिगत सड़क किनारे, नालियों एवं फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए गए है।

नगर मजिस्ट्रेट हर गिरी की नेतृत्व में देवपुरा चौक से रेलवे स्टेशन से शिवमूर्ति होते हुए वाल्मीकि चौक (ललतारौ पुल) तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान सड़क किनारे, फुटपाथ एवं नालियों के ऊपर संचालित 60 से अधिक अस्थाई अतिक्रमणों को हटाया गया एवं 15 से अधिक ठेलियों जब्त किया गया। इस अभियान में नगर निगम, पुलिस एवं जिला प्रशासन टीमों द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। नगर निगम एवं जिला प्रशासन की ओर से सभी संबंधित व्यक्तियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि भविष्य में नाली के ऊपर अथवा नाली की सीमा से बाहर किसी भी प्रकार का सामान, निर्माण सामग्री अथवा व्यावसायिक सामग्री रखी जाती है तो उसे तत्काल जब्त करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। साथ ही बार-बार अतिक्रमण किए जाने की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध तहरीर देकर विधिक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाएगी। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान सिटी उप नगर आयुक्त दीपक गोस्वामी, मुख्य सफाई निरीक्षक संजय शर्मा सहित पुलिस प्रशासन तथा नगर निगम हरिद्वार की टीम उपस्थित रही।

पुहाना एवं सालियर बाईपासपर चला अभियान

संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने अवगत कराया है कि जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में तहसीलदार के नेतृत्व में तहसील रुड़की के अतंर्गत पुहाना एवं सालियर बाईपास क्षेत्रांतर्गत अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान तहसील प्रशासन,पुलिस विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग की टीम द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया गया ,अभियान के दौरान सड़क किनारे किए गए स्थाई एवं अस्थाई अतिक्रमणों को जेसीबी के माध्यम से हटाया गया। इस अभियान में अपर तहसीलदार कानूनगो, राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी भी मौजूद रहे।

लक्सर मुख्य बाजार से रेलवे स्टेशन तक चला अभियान

उप जिलाधिकारी लक्सर अनिल शुक्ला ने अवगत कराया है कि उनके नेतृत्व में तहसीलदार एवं पुलिस टीम के साथ आज लक्सर में मेन मार्केट ओवर ब्रिज से रेलवे स्टेशन तक सड़क किनारे किए गए 55 से अधिक अवैध अतिक्रमण को हटाया गया, इस दौरान 05 लोगों के चालान करते हुए 9 हजार की धनराशि वसूली गई तथा एक व्यक्ति द्वारा घरेलू सिलेंडर का व्यवसायिक उपयोग करते हुए जब्त किया गया। इस दौरान तहसील प्रशासन,नगर पालिका,पुलिस सहित समंधित अधिकारी एवं कर्मचारी भी मौजूद रहे।

भगवानपुर नगर पंचायत में रायपुर चौक तक अभियान

उप जिलाधिकारी भगवानपुर देवेंद्र सिंह नेगी ने अवगत कराया है कि तहसीलदार दयाराम के नेतृत्व में आज भगवानपुर टोल प्लाजा से रायपुर चौक तक सर्विस रोड पर चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान, जिसमें 11 लोगों के चालान करते हुए 12 हजार की धनराशि वसूली गई साथ ही 17 नग समान भी जब्त किया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सड़क,नालियों एवं फुटपाथ के ऊपर से अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान नगर पंचायत के अधिकारी, पुलिस की टीम एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

एक नजर

कांवड़िये को गोली मारने वाला एक और आरोपी गिरफ्तार

पथ प्रवाह, हरिद्वार। पुलिस मुख्यालय द्वारा संचालित ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस की अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में गुरुकुल कांगड़ी क्षेत्र में कांवड़ियों पर फायरिंग और मारपीट के मामले में कनखल पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, 1 जून को गुरुकुल कांगड़ी क्षेत्र में कांवड़ियों के साथ कहासुनी के बाद फायरिंग, मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने की घटना हुई थी। फायरिंग में एक कांवड़िया घायल हो गया था। मामले में कोतवाली कनखल में मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक कनखल के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया। सादे वस्त्रों में तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा जगजीतपुर, पीठ पुलिया, फुटबॉल ग्राउंड और गुरुकुल कांगड़ी क्षेत्र में लगातार निगरानी एवं चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में अब तक मुख्य आरोपी सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, पिल्ला गैंग से जुड़े विभिन्न मामलों में अब तक कुल 22 बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी की पहचान जतिन पुत्र पवन कुमार निवासी जमालपुर कला, थाना कनखल, जनपद हरिद्वार के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन प्रहार के तहत शराब तस्करों, वारंटियों, हिस्ट्रीशीटरों, वांछित अभियुक्तों, गुंडा तत्वों, इनामी अपराधियों और हुड़दंगियों के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा। हर गिरफ्तारी के साथ अपराध के नेटवर्क पर निर्णायक चोट की जा रही है।

पीसीएस परीक्षा पास कर अधिकारी बने अभिषेक अग्रवाल का किया सम्मान

पथ प्रवाह, हरिद्वार। वैश्य एकता परिषद के पदाधिकारियों ने पीसीएस परीक्षा पास कर अधिकारी बने लक्सर के निरंजनपुर निवासी अभिषेक अग्रवाल के आवास पर पहुंचकर पुष्प गुच्छ भेंटकर एवं शॉल ओढ़ाकर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री वैश्य बंधु समाज मध्य क्षेत्र हरिद्वार के संस्थापक अशोक अग्रवाल ने कहा कि चुनौतीपूर्ण पीसीएस परीक्षा पास कर अधिकारी बने अभिषेक अग्रवाल ने समस्त वैश्य समाज का मान बढ़ाया है। अशोक अग्रवाल ने कहा कि एकाग्रता और कड़ी मेहनत से ही सफलता प्राप्ति होती है। वैश्य समाज के युवक और युवतियां निरंतर समाज का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। शिक्षित समाज ही राष्ट्र की उन्नति में योगदान देता है। उन्होंने अभिषेक अग्रवाल के माता-पिता की प्रशंसा करते हुए कहा कि अभिभावक ही बच्चों का भविष्य निर्धारण करते हैं। देश सेवा से जुड़ी सेवाओं में वैश्य समाज अपना योगदान प्रदान कर रहा है। वैश्य एकता परिषद के संयोजक पराग गुप्ता एवं लकसर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन अमरीश गर्ग ने अभिषेक अग्रवाल और उनके परिवार को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षा उन्नति का सबसे सशक्त माध्यम है।

सनातन धर्म ही भारत की आत्मा है- श्रीमहंत रविंद्रपुरी

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

श्री अखंड परशुराम अखाड़े के पदाधिकारियों ने निरंजनी अखाड़ा पहुंचकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्र पुरी महाराज और निरंजनी अखाड़े के स्वामी कार्तिक गिरी महाराज से भेंटकर आशीर्वाद लिया। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि सनातन धर्म ही भारत की आत्मा है। युवाओं को नशे और कुसंगति से दूर रहकर गौ माता और देश की सेवा करनी चाहिए। सनातन की रक्षा के लिए ऐसे संगठनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। श्री अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित कौशिक ने कहा कि अखाड़े का उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं को घर-घर तक पहुंचाना है। गौ सेवा और राष्ट्र सेवा ही संगठन की प्राथमिकता है। सनातन का ध्वज ऊंचा रखने के लिए हर सभी संभव प्रयास किए जाएंगे। पंडित अधीर कौशिक ने कहा कि हरिद्वार धर्मनगरी करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। नशे और नॉनवेज की आनलाइन डिलीवरी की वहज से धर्मनगरी की मर्यादा को ठेस पहुंच रही। जिसे पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना चाहिए। नशे और नॉनवेज पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के साथ ऑनलाइन डिलीवरी करने वाली कंपनियों पर भी रोक लगाई जाए। जो कंपनियां ऑनलाइन नॉनवेज की डिलीवरी कर रही हैं। सरकार को उन्हें तत्काल नोटिस भेजना चाहिए और पार्सल/फूड डिलीवरी ऐप पर पाबंदी लगानी चाहिए। श्री हिंदू तख्त के प्रधान यश देव कौशिक ने कहा कि संतों के मार्गदर्शन में संगठन सनातन हिंदू परंपरांओं को आगे बढ़ाने का काम करेगा। इस अवसर पर हर्ष शर्मा, साजन बजरंगी, वरुण चढ्ढ़ा, कार्तिक पंडित, अमित शर्मा, कृष्णा शर्मा, सूरज शर्मा और ऋषि शर्मा मौजूद रहे।

हरिद्वार में मिलावटखोरों पर चला प्रशासन का चाबुक ताबड़तोड़ छापेमारी, दो के खिलाफ कोर्ट केस

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

जनपद में आम जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों और अस्वच्छता फैलाने वाले रेस्टोरेंट संचालकों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बेहद सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के कड़े दिशा-निर्देशों के अनुपालन में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शनिवार को नेशनल हाईवे-58 (NH-58) क्षेत्र में एक बड़ा छापेमारी अभियान चलाया। इस अचानक हुई कार्रवाई से हाईवे किनारे स्थित ढाबों, होटलों और बेकरी संचालकों में हड़कंप मच गया।

सहायक आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) महिमानंद जोशी ने मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन में वरिष्ठ अधिकारियों की एक विशेष टीम गठित की गई थी। इस टीम ने ज्वालापुर से लेकर बहादराबाद टोल प्लाजा के बीच संचालित कुल छह प्रमुख खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने किचन की साफ-सफाई, कच्चे माल की गुणवत्ता, खाद्य पदार्थों के भंडारण की स्थिति और जरूरी प्रशासनिक दस्तावेजों की गहनता से पड़ताल की। निरीक्षण के दौरान कई जगह खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियमों की धज्जियां उड़ती मिलीं। टीम ने संदेह के आधार पर तत्काल दो संदिग्ध खाद्य पदार्थों के नमूने (सैंपल) सील किए, जिन्हें जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। इसके अलावा, एक नामी प्रतिष्ठान में भयंकर गंदगी और अस्वच्छता पाए जाने पर उसे तत्काल सुधार नोटिस जारी किया गया। नियमों के उल्लंघन पर एक चालान काटा गया, जबकि गंभीर अनियमितताएं बरतने वाले दो बड़े खाद्य कारोबारियों के खिलाफ विभाग ने सीधे न्यायालय में वाद (मुकदमा) दायर करने की बड़ी विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

सहायक आयुक्त महिमानंद जोशी ने साफ लफ्जों में चेतावनी दी है कि जनपद के भीतर आम नागरिकों और तीर्थयात्रियों को सुरक्षित एवं उच्च गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मुनाफे के चक्कर में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले तत्वों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ यह दंडात्मक अभियान आने वाले दिनों में और अधिक तेजी से निरंतर जारी रहेगा।

कुंभ मेला-2027 राज्य की प्रतिष्ठा और आस्था से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजनः आयुक्त गढ़वाल

कुंभ मेला–2027 की तैयारियों में समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित करें सभी विभाग

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

कुंभ मेला-2027 के आयोजन के लिए राज्य सरकार, भारत सरकार के विभिन्न विभागों, एजेंसियों तथा संबंधित संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित करने और तैयारियों की प्रगति की समीक्षा के उद्देश्य से आयुक्त गढ़वाल मंडल आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समन्वय समिति की बैठक सीसीआर सभागार में आयोजित की गई।

बैठक में कुंभ मेला-2027 से संबंधित विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कार्यों, प्रस्तावित योजनाओं तथा आगामी कार्ययोजना की विस्तृत समीक्षा की गई। इस अवसर पर आयुक्त आनंद स्वरूप ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे अपने दायित्वों से जुड़े कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण करने के लिए प्रभावी कार्ययोजना के साथ आगे बढ़ें तथा प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करें। आयुक्त ने कहा कि कुंभ मेला-2027 राज्य की प्रतिष्ठा और आस्था से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन है। अब योजनाओं और प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के

साथ-साथ उन्हें धरातल पर उतारने की दिशा में तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है। प्रत्येक विभाग अपने अधीन प्रस्तावित कार्यों के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करे तथा उनकी नियमित समीक्षा सुनिश्चित करे। किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब स्वीकार्य नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि कुंभ मेला की तैयारियों की नियमित निगरानी के लिए प्रत्येक माह उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। आगामी बैठकों में संबंधित विभागों के केवल नामित नोडल अधिकारी ही प्रतिभाग करें। उन्होंने रेलवे, परिवहन तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर आगामी कार्यों की विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि आकस्मिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक व्यवस्थाएं तथा आपातकालीन कार्ययोजनाएं भी तैयार रखी जाएं। सभी विभाग इस आयोजन को केवल विभागीय कार्य न मानकर राज्य की प्रतिष्ठा से जुड़े दायित्व के रूप में लें तथा पूर्ण गंभीरता, प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ कार्य करते हुए समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित करें।

मेलाधिकारी ने किया वर्चुअल प्रतिभाग

बैठक में मेलाधिकारी सोनिका ने वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग करते हुए मेले की तैयारियों एवं विभिन्न व्यवस्थाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुंभ मेला के लिए रेल एवं सड़क परिवहन व्यवस्था तथा आपदा प्रबंधन की विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करने हेतु संबंधित विभागों एवं संगठनों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल की मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) विनीता श्रीवास्तव ने भी ऑनलाइन प्रतिभाग करते हुए कुंभ मेला को लेकर रेलवे द्वारा प्रस्तावित तैयारियों की जानकारी दी। बैठक में जिलाधिकारी देहरादून आशीष चौहान, जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर, एसएसपी (कुंभ) आयुष अग्रवाल तथा एसएसपी देहरादून प्रमेन्द्र डोबाल ने भी कुंभ मेला आयोजन की तैयारियों को लेकर उपयोगी सुझाव प्रस्तुत किए। नगर आयुक्त हरिद्वार नंदन कुमार ने इस अवसर पर कुंभ मेला के दौरान सफाई, सैनिटेशन व्यवस्था तथा ठोस अपशिष्ट (कूड़ा) प्रबंधन से संबंधित तैयारियों की जानकारी दी। अपर मेलाधिकारी दयानंद सरस्वती ने बैठक में कुंभ मेला-2027 के लिए स्वीकृत कार्यों की प्रगति एवं विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। मेला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज कुमार वर्मा, रेलवे के एडीआरएम पी.एस. झा, मेला अधिष्ठान के वित्त नियंत्रक लखेन्द्र गौथियाल सहित अन्य अधिकारियों ने भी कुंभ मेला से संबंधित विभागीय तैयारियों एवं कार्यों की प्रगति से अवगत कराया। बैठक में कुंभ मेला की व्यवस्थाओं से जुड़े राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ ही वर्चुअल माध्यम से टिहरी व पौड़ी गढवाल जनपदों के जिला प्रषासन व पुलिस विभाग के अधिकारियों ने भी प्रतिभाग किया।

एक नजर

सीवरेज के लिए खोदी गई सड़क एक दिन में 160 मीटर की तैयार

पथ प्रवाह, हरिद्वार। हरिद्वार शहर के अंतर्गत सीवरेज कार्य हेतु खोदी गई सड़कों से क्षेत्रीय जनता, व्यापारियों को हो रही परेशानी के दृष्टिगत जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने चल रहे निर्माण कार्यों को त्वरित गति से दिन रात कार्य करते हुए पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों एवं कांट्रेक्टर को दिए हैं। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए है की चारधाम यात्रा के दृष्टिगत सीवरेज कार्य हेतु जो भी सड़के खोदी गयी है उन सड़कों का हर हाल में मरम्मत कार्य पूर्ण कर लिया जाए,जिसके अनुपालन में कार्य तीव्र गति से किए जा रहे है। परियोजना प्रबंधक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई गंगा उत्तराखंड पेयजल निगम मिनाक्षी मित्तल ने अवगत कराया है कि जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में केएफडब्लयू वित्त पोषित हरिद्वार जलोत्सारण योजना पैकेज 01 एवं पैकेज 02 के अंतर्गत कराए जा रहे सड़क पुनर्निर्माण संबंधी कार्य जिसके तहत 05 जून को किए गए निर्माण कार्यों का विवरण निम्नवत है जिसमें- पैकेज 01 के अंतर्गत एनएचएआई नियर जैन मंदिर बीटी रोड 60 मीटर कार्य पूर्ण कर लिया गया है,कुल 60 मीटर कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा पैकेज 02 के अंतर्गत गणपतिधाम फेस 3 सीसी रोड 30 मीटर, गणपति धाम फेस 3 पावर ब्लॉक 25 मीटर, मोहन इंक्लेव सीसी रोड 45 मीटर कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा कुल 100 मीटर कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सड़कों का कार्य दिन-रात त्वरित गति से किए जा रहे है।

चारधाम यात्रा के लिए 5484 ने कराया पंजीकरण

पथ प्रवाह, हरिद्वार। हरिद्वार ऋषिकुल मैदान में बनाए गए यात्री पंजीकरण केंद्र में शनिवार को चारधाम यात्रा के लिए 5484 यात्रियों ने अपना पंजीकरण कराया। जिन यात्रियों ने पंजीकरण कराया उनमें यमुनोत्री धाम के लिए 905, गंगोत्री धाम के लिए 942, केदारनाथ धाम के लिए 1630, बद्रीनाथ धाम के लिए 1950 और हेमकुंड साहिब के लिए 57 पंजीकरण शामिल हैं। इस तरह विभिन्न राज्यों से आए 5484 यात्रियों द्वारा चारधाम के लिए आज अपना पंजीकरण कराया गया। ऋषिकुल मैदान यात्री पंजीकरण केंद्र से अब तक कुल 3 लाख 90 हजार 7 सौ 74 यात्रियों ने चारधाम यात्रा के लिए अपना पंजीकरण कराया है।

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए की बैठक

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

जनपद में विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अमित कुमार चंद (डीईओ बेसिक) की अध्यक्षता में (S.I.R- Special Intensive RevisionI) विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में एक आवश्यक बैठक का आयोजन नेहरू मेमोरियल जूनियर स्कूल, बहादरपुर जट्ट, हरिद्वार में किया गया। बैठक में बूथ संख्या 72 से 90 तक के सभी सुपरवाइजर एवं सभी बीएलओ ने प्रतिभाग किया।

बैठक में सभी बीएलओ ने अपने-अपने बूथ से संबंधित समस्याएं बताई और अधिकारी ने उन समस्याएं के समाधान का तरीका बताया तथा साथ ही सभी सुपरवाइजर्स ने अपने अनुभवों से अवगत कराया। बैठक के अंत में सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अमित कुमार चंद ने उपस्थित सभी

सुपरवाइजर्स एवं सभी बीएलओ को आवश्यक दिशा निर्देश कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए अपने दायित्वों का भली भांति निर्वहन करें। बैठक में सभी बीएलओ पर्यवेक्षक मोनिका सैनी, तेलूराम, संजीव कुमार एवं आशीष कुमार लोहट तथा सभी बीएलओ सुंदरपाल चौधरी, ललिता चमोली, गुड्डी देवी, ममता, मंजू डोभाल, शकुंतला नेगी, सुभद्रा रवि, पोपिंदर, बलिराम, प्रमिला, उमेश देवी, रेखा, सुनीता, रीना, रेखा सैनी, नंदकिशोर, भावना,अनीता, मुकेश देवी आदि उपस्थित रहे। बैठक का सफल आयोजन एवं संचालन आशीष कुमार लोहट (बीएलओ पर्यवेक्षक) ने किया।

उपभोक्ताओं की सहमति के बिना ना लगाए जांए स्मार्ट मीटर-बालेश्वर सिंह

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

प्रैस क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालेश्वर सिंह ने कहा कि स्मार्ट मीटर जनता पर थोपा नहीं जाना चाहिए। ऊर्जा निगम पुलिस की सहायता लेकर स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी कर रहा है। जिन उपभोक्ताओं के मीटर ठीक काम कर रहे हैं। उन्हें बदलने का कोई औचित्य नहीं है। विद्युत विभाग को उपभोक्ताओं की सहमति से ही स्मार्ट मीटर लगाने चाहिए।

उन्होंने कहा कि यदि किसी उपभोक्ता की सहमति के बिना स्मार्ट मीटर लगाया गया तो कांग्रेस विरोध करेगी। स्मार्ट मीटर के बिलों को लेकर लेकर भी मतभेद बने हुए हैं। बालेश्वर सिंह ने कहा कि अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों का रोजगार प्रभावित नहीं होना चाहिए व्यापारियों की मांग को भी सुनना चाहिए। व्यापारियों का उत्पीड़न किसी भी रूप में सहन नहीं किया जाएगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनोज सैनी एवं सोम त्यागी ने कहा कि शहर भर में पुराने मीटर लगे हुए हैं और सही चल रहे हैं। इसके बावजूद स्मार्ट मीटर लगाने की जोर जबरदस्ती क्यों की जा रही है। जबकि लोग लगातार स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को जनता के हितों में फैसले लेने चाहिए। मनोज सैनी ने अवैध अतिक्रमण

ही हटाना चाहिए। रसूखदार लोगों के अतिक्रमण पर भी प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। लोगों का रोजगार उजाड़ने से पहले बसाने की बात होनी चाहिए। अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न ना किया जाए। वरना कांग्रेस जनता के संघर्ष से पीछे नहीं हटेगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजय सैनी ने कहा कि वर्तमान मास्टर प्लान जनता के हितों को देखते हुए नहीं बनाया गया है। लोगों के रोजगार को देखकर योजनाएं लागू होनी चाहिए। मास्टर प्लान में बड़े निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई है जो कि विकास में प्रमुख बाधा है। आवास निर्माण, होटल, गेस्ट हाउस, बड़ी गतिविधियां मास्टर प्लान से प्रभावित होंगी। संजय सैनी ने कहा कि भू उपयोग परिवर्तन नियमों के चलते व्यापार निर्माण श्रमिक कार्य प्रभावित होंगे। आवास विभाग द्वारा भू उपयोग शुल्क में 567 प्रतिशत की बढ़ोतरी का शासनादेश तुरंत निरस्त किया जाना चाहिए। जनता के हितों में फैसला नहीं लिए जा रहे हैं। कैलाश प्रधान एवं सतीश दुबे ने कहा कि महंगाई से जनता परेशान है। सरकार महंगाई को नियंत्रित नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि वीआईपी मूवमेंट से लोगों के कार्य प्रभावित नहीं होने चाहिए। जनता के काम ना रुके इसको लेकर अतिरिक्त अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। प्रेस वार्ता के दौरान डा.मेहरबान, सुनील चौहान, अशोक धींगान, राजेंद्र, सुनील चौहान आदि मौजूद रहे।

संपादकीय

आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपैया के चक्कर में फंसी अर्थ -व्यवस्था

भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर आज देश में एक गंभीर बहस चल रही है। एक पक्ष का मानना है, कि 2004 से 2014 के बीच, विशेषकर 2011 तक, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल थी। उस दौर में भारत की तुलना चीन, अमेरिका, रुस एवं अन्य यूरोपीय देशों के साथ वैश्विक मंचों पर होने लगी थी। सूचना प्रौद्योगिकी, सेवा क्षेत्र, विनिर्माण तथा लघु एवं मध्यम उद्योगों के विस्तार ने देश को नई आर्थिक ऊँचाइयों तक पहुँचाया था। 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान जब अमेरिका और यूरोप की बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ संकट से जूझ रही थीं, तब भारत अपेक्षाकृत मजबूत आर्थिक स्थिति के साथ खड़ा दिखाई दिया। अनेक अर्थशास्त्रियों का मानना था, भारत के विशाल घरेलू बाजार, असंगठित क्षेत्र तथा लघु एवं मध्यम उद्योगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यही कारण था, उस समय भारत को वैश्विक आर्थिक क्षेत्र के केंद्र बिन्दू के रूप में देखा जाने लगा था। लेकिन 2011 के बाद भारत का राजनीतिक माहौल तेजी से बदला। भ्रष्टाचार के आरोप, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्टों तथा अन्ना हजारे के नेतृत्व में चले जनलोकपाल आंदोलन ने तत्कालीन सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया। सरकार की छवि पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इसमें विदेशी ताकतों का हाथ भी बताया जाता है। कारपोरेट जगत भी मनमोहन सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया था। इस तरह से सारा विपक्ष कांग्रेस और मनमोहन के खिलाफ खड़ा हो गया था। अंततः 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ। आलोचकों का आरोप है कि उस समय देश की आडिट रिपोर्ट में लगाए गए कई आर्थिक नुकसान के अनुमान न्यायिक प्रक्रिया में प्रमाणित नहीं हो सके, काल्पनिक आरोपों से तब तक राजनीतिक माहौल पूरी तरह बदल चुका था।

वर्तमान आर्थिक परिदृश्य को लेकर भी गंभीर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि पिछले एक दशक में ऐसी नीतियाँ अपनाई गईं, जिनसे बड़े कॉर्पोरेट समूहों को लाभ मिला, जबकि लघु एवं मध्यम उद्योगों तथा असंगठित क्षेत्र को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। नोटबंदी, जीएसटी के प्रारंभिक क्रियान्वयन और महामारी के प्रभाव ने छोटे व्यवसायों की कमर तोड़ दी। लाखों सूक्ष्म इकाइयाँ बंद हुईं। रोजगार के अवसर सिमटते चले गए। अर्थ-व्यवस्था में एक अन्य चिंता भारत के बढ़ते आयात और घटती विनिर्माण क्षमता को लेकर है। चीन से बड़े पैमाने पर उपभोक्ता वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक उत्पादों का आयात लगातार बढ़ा है। इसके विपरीत भारत की निर्यात वृद्धि अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पाई। इससे व्यापार घाटा बढ़ा है। जिससे आर्थिक आत्मनिर्भरता के दावों पर भी प्रश्नचिह्न लगा है। बढ़ती बेरोजगारी, महँगाई और घरेलू ऋण चिंता के विषय बने हुए हैं। किसानों को उनकी उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है। किसान कर्जदार और खेती मंहगी होती जा रही है। आम नागरिक की क्रय-शक्ति घट गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न और आवश्यक सेवाएँ लगातार महँगी होती जा रही हैं। दूसरी ओर, शेयर बाजार में तेजी और कॉर्पोरेट मुनाफों के बावजूद आम जनता की आर्थिक स्थिति में अपेक्षित सुधार दिखाई नहीं देता। इससे आर्थिक विकास और सामाजिक वास्तविकताओं के बीच का अंतर बढ़ गया है। आम आदमी की आय में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया की स्थिति बनी हुई है। आज आवश्यकता इस बात की है कि आर्थिक नीतियों का केंद्र केवल बड़े निवेश और कॉर्पोरेट लाभ न होकर रोजगार सृजन, लघु उद्योगों का संरक्षण, कृषि क्षेत्र की मजबूती तथा घरेलू मांग में विस्तार हो। भारत की वास्तविक शक्ति उसके करोड़ों छोटे उद्यमियों, किसानों, श्रमिकों और मध्यम वर्ग में निहित है। यदि आर्थिक विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुँचता, तो ऊँची विकास दर का सपना- सपना बनकर ही रह जायेगा। भारत के सामने चुनौती केवल विकास दर बढ़ाने की नहीं, बल्कि समावेशी और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने की है।

मालवीय नगर अग्निकांडः मुआवजे से नहीं, जवाबदेही और सुधार से बचेगी ज़िंदगी

डॉ. सत्यवान सौरभ

दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में 3 जून 2026 को लगी भीषण आग ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस दर्दनाक हादसे में इक्कीस लोगों की मौत और अनेक लोगों के घायल होने की खबर ने न केवल राजधानी बल्कि पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। आग की लपटों से बचने के लिए लोगों को ऊँची इमारत से कूदते हुए देखा गया। सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों में प्रसारित हुए दृश्य किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के लिए अत्यंत पीड़ादायक थे। यह केवल एक दुर्घटना नहीं थी; यह उस व्यवस्था की विफलता का भयावह प्रमाण थी जो नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।

हर बड़ी दुर्घटना के बाद कुछ दिन तक शोक, संवेदना, जांच और मुआवजे की घोषणाएं होती हैं। फिर धीरे-धीरे मामला सार्वजनिक स्मृति से ओझल हो जाता है। लेकिन मालवीय नगर की यह त्रासदी केवल शोक व्यक्त करके भुला देने योग्य घटना नहीं है। यह उन गहरे संरचनात्मक दोषों की ओर संकेत करती है जो भारत के महानगरों में तेजी से बढ़ते शहरीकरण के साथ और अधिक खतरनाक रूप धारण कर चुके हैं। यह हादसा हमें मजबूर करता है कि हम पूछें–क्या हमारी इमारतें वास्तव में सुरक्षित हैं? क्या अग्नि सुरक्षा नियम केवल कागजों तक सीमित हैं? और क्या प्रशासन की भूमिका केवल दुर्घटना के बाद राहत बांटने तक सीमित रह गई है?

किसी भी बहुमंजिला इमारत में आग लगने की स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है– सुरक्षित निकास, अग्निशमन उपकरण और समय पर बचाव। यदि किसी भवन में मौजूद लोगों को अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों और बालकनियों से छलांग लगानी पड़े, तो इसका अर्थ है कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी थी। आग केवल भवन को नहीं जलाती, वह सुरक्षा संबंधी दावों और प्रशासनिक तैयारियों की वास्तविकता भी उजागर कर देती है। मालवीय नगर की घटना में यही हुआ।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, होटल में कई विदेशी नागरिक भी ठहरे हुए थे। यह तथ्य इस त्रासदी को और गंभीर बना देता है। भारत की राजधानी दुनिया भर के पर्यटकों, व्यापारियों और निवेशकों का स्वागत करती है। ऐसे में यदि राजधानी में ही सुरक्षा मानकों की स्थिति इतनी कमजोर हो कि विदेशी नागरिक भी असुरक्षित महसूस करें, तो यह केवल स्थानीय प्रशासन की विफलता नहीं बल्कि देश की अंतरराष्ट्रीय छवि पर भी प्रश्नचिह्न है। आधुनिक महानगर की पहचान केवल ऊँची इमारतों और चमकदार होटलों से नहीं होती, बल्कि वहाँ उपलब्ध सुरक्षा और आपदा प्रबंधन प्रणाली से होती है।

इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शोक व्यक्त किया तथा मृतकों और घायलों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की। ऐसी संवेदनाएं आवश्यक हैं और संकट की घड़ी में पीड़ित परिवारों को सहायता मिलनी भी चाहिए। किंतु यह भी उतना ही सत्य है कि मुआवजा किसी खोए हुए जीवन को वापस नहीं ला सकता।

सोशल मीडिया पर बढ़ती सनसनी, स्क्रिप्टेड विवाद और दर्शकों की जिम्मेदारी

डॉ. प्रियंका सौरभ

डिजिटल क्रांति ने संचार और अभिव्यक्ति की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। आज एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन के सहारे कोई भी व्यक्ति अपने विचार, प्रतिभा और अनुभव दुनिया के सामने रख सकता है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया मंचों ने लाखों लोगों को पहचान, रोजगार और लोकप्रियता प्रदान की है। यह एक सकारात्मक परिवर्तन है जिसने पारंपरिक मीडिया के एकाधिकार को तोड़ा और आम नागरिक को भी अभिव्यक्ति का अवसर दिया। लेकिन इस परिवर्तन के साथ कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ भी विकसित हुई हैं जो चिंता का विषय बनती जा रही हैं। इनमें सबसे प्रमुख है– व्यूज़, लाइक्स और फॉलोअर्स की अंधी दौड़।

आज सोशल मीडिया पर सफलता का पैमाना अक्सर सामग्री की गुणवत्ता नहीं, बल्कि उसकी लोकप्रियता बन गया है। किसी वीडियो को कितने लोगों ने देखा, उस पर कितनी टिप्पणियाँ आईं और उसे कितनी बार साझा किया गया, यही उसकी सफलता का आधार माना जाता है। इस वातावरण में कुछ कंटेंट निर्माता दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसे तरीकों का सहारा लेने लगे हैं जो वास्तविकता से अधिक नाटक और सनसनी पर आधारित होते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया पर ऐसे अनेक वीडियो वायरल हुए हैं जिनमें कथित झगड़े, पारिवारिक विवाद, मित्रों के बीच टकराव, रिश्तों में दरार, सार्वजनिक बहस या भावनात्मक घटनाएँ दिखाई जाती हैं। कई बार ये घटनाएँ इतनी नाटकीय प्रतीत होती हैं कि दर्शकों के मन में स्वाभाविक रूप से संदेह पैदा होता है। ऐसा लगता है कि जैसे पूरा घटनाक्रम पहले से तय हो, संवाद लिखे गए हों और कैमरे केवल उस पटकथा को रिकॉर्ड करने के लिए लगाए गए हों।

अक्सर देखा जाता है कि कथित विवाद ठीक कैमरे या सीसीटीवी की मौजूदगी में घटित होता है। पात्र बार-बार कैमरे की ओर देखते हैं, घटनाएँ एकदम फिल्मी अंदाज़ में आगे बढ़ती हैं और अंत में वीडियो वायरल हो जाता है। दर्शक सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या यह वास्तव में अचानक हुई घटना थी या फिर लोकप्रियता हासिल करने के लिए रचा गया एक सुनियोजित नाटक?

सोशल मीडिया की आर्थिक संरचना इस प्रवृत्ति को समझने में मदद करती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ध्यान ही सबसे बड़ी पूँजी है। जितने अधिक लोग किसी सामग्री को देखेंगे, उतनी अधिक उसकी पहुँच होगी और उतना ही अधिक आर्थिक लाभ उससे जुड़ सकता है। विज्ञापन, ब्रांड सहयोग, प्रायोजन और अन्य व्यावसायिक अवसर लोकप्रियता के साथ बढ़ते हैं। ऐसे में कुछ लोग यह मान बैठते हैं कि यदि विवाद से व्यूज़ बढ़ते हैं तो विवाद पैदा करना ही सबसे आसान रणनीति है।

यही कारण है कि कई बार वास्तविक रचनात्मकता पीछे छूट जाती है और उसकी जगह कृत्रिम ड्रामा ले लेता है। ज्ञानवर्धक सामग्री तैयार करने, शोध करने या उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करने में समय और मेहनत लगती है। इसके विपरीत, एक विवादास्पद वीडियो या सनसनीखेज घटना कुछ ही घंटों में लाखों लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकती है। परिणामस्वरूप कुछ कंटेंट निर्माता आसान रास्ता चुन लेते हैं।

इस प्रवृत्ति का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव युवा पीढ़ी पर पड़ता है। किशोर और युवा सोशल मीडिया के सबसे सक्रिय उपभोक्ता हैं। जब वे देखते हैं कि विवाद, झगड़े और सनसनी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, तो उनके मन में यह धारणा बन सकती है कि सफलता का मार्ग प्रतिभा, मेहनत और ज्ञान नहीं, बल्कि ध्यान आकर्षित करने वाली गतिविधियाँ हैं। यह सोच समाज के लिए दीर्घकालिक रूप से नुकसानदेह साबित हो सकती है।

सोशल मीडिया पर बढ़ता यह नाटकीयकरण केवल मनोरंजन का प्रश्न नहीं है, बल्कि सामाजिक मूल्यों से भी जुड़ा हुआ है। जब कृत्रिम विवाद चर्चा का केंद्र बन जाते हैं, तब शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, रोजगार, विज्ञान और सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण विषय हाशिए पर चले जाते हैं। समाज का सामूहिक ध्यान उन मुद्दों से हटकर उन घटनाओं पर केंद्रित हो जाता है जिनका वास्तविक जीवन से बहुत कम संबंध होता है।

हालाँकि यह भी सच है कि हर वायरल वीडियो या सार्वजनिक विवाद को बिना प्रमाण स्क्रिप्टेड नहीं कहा जा सकता। वास्तविक जीवन में भी मतभेद होते हैं, रिश्तों में तनाव आता है और सार्वजनिक घटनाएँ घटित होती हैं। कैमरों की बढ़ती उपलब्धता के कारण अनेक वास्तविक घटनाएँ रिकॉर्ड भी हो जाती हैं। इसलिए किसी भी वीडियो के बारे में निष्कर्ष निकालते समय संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। केवल अनुमान के आधार पर किसी व्यक्ति या समूह को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा।

लेकिन जब बार-बार एक जैसे पैटर्न दिखाई दें, जब हर विवाद वायरल होने की क्षमता से भरपूर हो, जब हर झगड़ा कैमरे के सामने ही घटित हो और जब संबंधित लोग बाद में उस विवाद से आर्थिक या सामाजिक लाभ प्राप्त करते दिखाई दें, तब प्रश्न उठना स्वाभाविक है। लोकतांत्रिक समाज में प्रश्न पूछना और तथ्यों की पड़ताल करना दर्शकों का अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी।

यहीं मीडिया साक्षरता का महत्व सामने आता है। आज केवल साक्षर होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि डिजिटल साक्षर होना भी आवश्यक है। लोगों को यह समझना चाहिए कि सोशल मीडिया की सामग्री कैसे तैयार होती है, एल्गोरिद्म किस प्रकार काम करते हैं और कौन-से तत्व किसी सामग्री को वायरल बनाते हैं। यदि दर्शक इन प्रक्रियाओं को समझेंगे, तो वे सनसनी और वास्तविकता के बीच अंतर करने में अधिक सक्षम होंगे।

यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म्स की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। यदि उनके एल्गोरिद्म केवल उन सामग्रियों को बढ़ावा देंगे जो अधिक विवादास्पद और उत्तेजक हैं, तो कंटेंट निर्माता भी उसी दिशा में बढ़ेंगे।

मिलावट-मुक्त भारत से ही विकसित भारत संभव

ललित गर्ग

हर वर्ष 7 जून को मनाया जाने वाला विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस केवल सुरक्षित भोजन की आवश्यकता का स्मरण कराने वाला दिवस नहीं है, बल्कि यह मानव स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, आर्थिक समृद्धि और सतत विकास के लिए एक वैश्विक संकल्प का अवसर भी है। वर्ष 2026 की थीम ''खाद्य सुरक्षाः विज्ञान की सक्रिय भूमिका'' इस बात पर बल देती है कि विज्ञान, अनुसंधान, तकनीक और प्रभावी निगरानी प्रणालियों के माध्यम से ही सुरक्षित खाद्य व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है। लेकिन विडम्बना यह है कि भारत जैसे विशाल कृषि प्रधान देश में खाद्य पदार्थों, दवाइयों और दैनिक उपभोग की वस्तुओं में बढ़ती मिलावट इस लक्ष्य को गंभीर चुनौती दे रही है। मिलावट केवल खाद्य सुरक्षा का प्रश्न नहीं है, यह राष्ट्र के स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, नैतिकता और वैश्विक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ विषय है। जिस देश को विश्वगुरु और विकसित भारत बनने का सपना है, वहां यदि दूध, घी, मावा, मसाले, अनाज, मिठाइयां, फल-सब्जियां और यहां तक कि जीवनरक्षक दवाइयां भी मिलावट की शिकार हों, तो यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। यह केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि मानवता के विरुद्ध अपराध है।

भारत में मिलावट का कारोबार आज एक संगठित आर्थिक अपराध का रूप ले चुका है। दूध में डिटर्जेंट, यूरिया और सिंथेटिक रसायनों का प्रयोग, मावे में स्टार्च और रासायनिक पदार्थों की मिलावट, मसालों में रंग और धूल, शहद में चीनी सिरप, खाद्य तेलों में सस्ते तेलों का मिश्रण तथा फलों और सब्जियों को कृत्रिम रसायनों से पकाना आम बात हो गई है। बाजार में बिकने वाले अनेक उत्पाद देखने में आकर्षक होते हैं, लेकिन भीतर से विषैले सिद्ध होते हैं। स्थिति तब और भयावह हो जाती है जब दवाइयों में मिलावट या नकली दवाओं का मामला सामने आता है। पिछले वर्षों में विभिन्न राज्यों में नकली अथवा घटिया दवाओं के सेवन से अनेक लोगों की मृत्यु और गंभीर स्वास्थ्य संकट की घटनाएं सामने आईं। राजस्थान के कोटा सहित कई स्थानों पर ऐसी खबरों ने पूरे देश को झकझोर दिया। जब जीवन बचाने वाली दवा ही मौत का कारण बनने लगे, तब यह केवल स्वास्थ्य व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि सामाजिक संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है।

मिलावट का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। कैंसर, किडनी रोग, हृदय रोग, यकृत संबंधी विकार, हार्मोन असंतुलन, बच्चों में कुपोषण, महिलाओं में स्वास्थ्य समस्याएं तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी जैसी अनेक गंभीर समस्याओं का संबंध दूषित एवं मिलावटी खाद्य पदार्थों से जुड़ता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार असुरक्षित भोजन के कारण हर वर्ष करोड़ों लोग बीमार पड़ते हैं। भारत में भी स्वास्थ्य पर पड़ने वाला यह बोझ लगातार बढ़ रहा है। किन्तु मिलावट का संकट केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। यह देश की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रहार करता है। जब किसी देश के खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता संदिग्ध हो जाती है, तब अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसकी विश्वसनीयता प्रभावित होती है। निर्यात घटता है, विदेशी निवेश प्रभावित होता है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश पिछड़ जाता है। भारत कृषि उत्पादों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का एक बड़ा केंद्र बन सकता है, लेकिन मिलावट की समस्या उसकी संभावनाओं पर ग्रहण लगा रही है।

इससे भी अधिक चिंता का विषय यह है कि मिलावट सामाजिक मूल्यों के क्षरण का प्रतीक बनती जा रही है। कुछ लोग त्वरित लाभ और अधिक मुनाफे की लालसा में दूसरों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। यह केवल आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि नैतिक पतन का भी संकेत है। जब समाज में ईमानदारी और उत्तरदायित्व की भावना कमजोर पड़ती है, तब ऐसे अपराध फलने-फूलने लगते हैं। सरकारों ने समय-समय पर खाद्य सुरक्षा और मानक कानून बनाए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) सहित अनेक संस्थाएं निगरानी और परीक्षण का कार्य करती हैं। फिर भी जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, निरीक्षण तंत्र की कमजोरी और कानूनी प्रक्रियाओं की धीमी गति मिलावट के विरुद्ध अभियान को प्रभावी नहीं बनने देती। अनेक मामलों में दोषियों को दंड मिलने में वर्षों लग जाते हैं, जिससे अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं।

आज आवश्यकता केवल कानून बनाने की नहीं, बल्कि उन्हें कठोरता और पारदर्शिता के साथ लागू करने की है। खाद्य पदार्थों की नियमित जांच, आधुनिक प्रयोगशालाओं का विस्तार, डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली, त्वरित न्याय व्यवस्था और दोषियों के लिए कठोर दंड आवश्यक हैं। मिलावट को सामान्य आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य के विरुद्ध गंभीर अपराध माना जाना चाहिए। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2026 की थीम विज्ञान की भूमिका पर जोर देती है। विज्ञान और तकनीक मिलावट के विरुद्ध सबसे प्रभावी हथियार बन सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ब्लॉकचेन आधारित आपूर्ति श्रृंखला, आधुनिक परीक्षण तकनीक, मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब तथा उपभोक्ता जागरूकता एप्लिकेशन खाद्य सुरक्षा को नई दिशा दे सकते हैं। वैज्ञानिक निगरानी से उत्पादन से लेकर उपभोग तक हर चरण में गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है। लेकिन केवल सरकार या विज्ञान ही इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते।

समाज और उपभोक्ताओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। जागरूक नागरिकों को संदिग्ध उत्पादों की शिकायत करनी चाहिए, प्रमाणित उत्पादों का उपयोग करना चाहिए तथा स्थानीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा के प्रति जनजागरण अभियान चलाने चाहिए। विद्यालयों, महाविद्यालयों, सामाजिक संस्थाओं और धार्मिक संगठनों को भी इस विषय को सामाजिक आंदोलन का रूप देना होगा।

भारत आज विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

देवभूमि उत्तराखंड सदियों से साहित्य, संस्कृति और सृजन की भूमिः सीएम धामी

पथ प्रवाह, हल्द्वानी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कालाढुंगी के नमस्ते कॉर्बेट रिज़ॉर्ट धनपुर धमोला पहुंचकर ललित फाउंडेशन के पंचम अधिवेशन 'अभिव्यंजना' 5ज0 का दीप जलाकर शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि ये केवल एक कवि सम्मेलन नहीं बल्कि विचारों, भावनाओं और सृजनशीलता को अनुभव करने का एक अभिनव अवसर है। उन्होंने कहा कि कवि केवल शब्दों के निर्माता नहीं होते बल्कि वे समाज के चिंतक, मार्गदर्शक और प्रेरक भी होते हैं क्योंकि, कवि की रचनाएं समाज को दर्पण दिखाने का काम करती हैं। उन्होंने कहा कि जब समाज उलझनों से घिरता है, तब कवि अपनी लेखनी से न केवल समाज को नई दिशा दिखाने का काम करता है, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास भी करता है। उन्होंने कहा कि इतिहास साक्षी है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को भी तभी गति मिली जब हमारे कवियों और साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं से देशवासियों को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया और आज ऐसे ही राष्ट्रभक्त एवम्

विशिष्ट कवियों का समुच्चय हमारे सम्मुख उपस्थित है। जिनकी वाणी में विरह है तो प्रेम भी है,विद्रोह है तो देशभक्ति भी है,हास्य है तो भक्ति भी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ओर जहां डॉ. कुमार विश्वास जी ने अपनी लेखनी और विशिष्ट प्रस्तुति शैली के माध्यम से कविता को नई पहचान दी है, वहीं पदमश्री अशोक चक्रधर जी की रचनाएँ हास्य, व्यंग्य और सामाजिक सरोकारों का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती हैं। उन्होंने कहा कि डॉ. हरिओम पंवार जी की ओजस्वी कविताएँ राष्ट्रभक्ति और जनचेतना की सशक्त अभिव्यक्ति हैं, जो हर श्रोता को ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करती हैं।

उन्होंने कहा कि सभी कवियों ने कविताओं को विशिष्ट मंचों से निकालकर जन-जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करने के साथ-साथ युवाओं को साहित्य से जोड़ने का सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड सदियों से साहित्य, संस्कृति और सृजन की भूमि रही है। हिमालय की गोद में बसी इस पावन धरती ने अनेक ऐसे साहित्यकार, कवि और लोकचिंतक दिए हैं, जिन्होंने अपनी लेखनी से समाज को दिशा देने का कार्य किया है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि चाहे सुमित्रानंदन पंत जी की प्रकृति-साधना हो, चंद्रकुंवर बर्त्वाल जी की काव्य चेतना हो, गिर्दा की जन सरोकारों को उठाती रचनाएं हों, शैलेश मटियानी जी का उत्तराखंडी लोकजीवन का सशक्त चित्रण हो, गौरा पंत 'शिवानी' जी की साहित्य-साधना हो, मोहन उप्रेती जी द्वारा लोक संस्कृति के संरक्षण का अद्भुत प्रयास हो। उन्होंने कहा कि देवभूमि ने अपनी साहित्यिक चेतना और सृजनधारा से सदैव देश-विदेश के साहित्य प्रेमियों को आकर्षित किया है। उत्तराखंड की साहित्यिक परंपरा आज भी नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ते हुए राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा दे रही है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज और साहित्य के क्षेत्र में प्रेरणादायी कार्य कर रहे कवि, कवित्रियों एवम् साहित्यकारों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान मात्र व्यक्तियों का नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाली सोच का सम्मान है। उन्होंने सम्मानित होने वाले सभी समाजसेवियों और साहित्यकारों को हार्दिक बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यहाँ ऐसे प्रख्यात कवि उपस्थित हैं, जो प्रस्तुति देते हैं तो उनकी कविताएँ मात्र पंक्तियाँ नहीं रह जातीं, बल्कि जनमानस के लिए प्रेरणा और परिवर्तन का स्वर बन जाती हैं। उन्होंने साहित्य संगम को एक नई चेतना, नई ऊर्जा और अपने 'विकल्प रहित संकल्प' के साथ और आगे लेकर जाने का आह्वान किया।इससे पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा देवभूमि आगमन पर इस कवियों एवं साहित्यकारों का स्वागत किया।

इस अवसर पर विधायक कालाढुंगी बंशीधर भगत, कवि डॉ कुमार कुमार विश्वास, पद्मश्री अशोक चक्रधर, डॉ हरिओम पवार सहित देश के विभिन क्षेत्रों से आए कवि एवं साहित्यकार व अन्य उपस्थित रहे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आईआरबी बेलपडाव, रामनगर पहुंचने पर विधायक बंशीधर भगत, बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, उपाध्यक्ष गणेश रावत, दर्जा राज्यमंत्री सुरेश भट्ट, शंकर कोरंगा, सुरेंद्र नामधारी,हुकुम सिंह कुँवर आयोग के सदस्य जेडए वारसी, मंडलायुक्त दीपक रावत, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, एसएसपी डॉ.मंजूनाथ टीसी, मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडेय सहित विभिन्न जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों ने पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका स्वागत किया।

पर्यावरण संरक्षण के लिए जनभागीदारी और सामूहिक प्रयास आवश्यकः त्रिवेंद्र

पथ प्रवाह, देहरादून।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दून विश्वविद्यालय परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत तथा विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल ने विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के साथ वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भविष्य का संदेश दिया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपित किए गए तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिवस विशेष का विषय नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का सतत दायित्व है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वच्छता एवं सतत विकास के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण पहल कर रहा है। आज जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण एवं प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण जैसी चुनौतियां संपूर्ण मानवता के सामने गंभीर संकट के रूप में खड़ी हैं, जिनका समाधान केवल जनभागीदारी और सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। उन्होंने कहा कि हमें अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण संरक्षण को व्यवहार का हिस्सा बनाना होगा। वृक्षारोपण, जल संरक्षण, प्लास्टिक के उपयोग में कमी, कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन एवं स्वच्छता जैसे प्रयासों को

जन आंदोलन का स्वरूप देने की आवश्यकता है। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। उन्होंने कचरा प्रबंधन के वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने तथा पर्यावरणीय जागरूकता अभियानों को गांव-गांव और जन-जन तक पहुंचाने पर बल दिया।

सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित करना ही मानव जीवन की स्थिरता और समृद्धि का आधार है। पर्यावरण संरक्षण ही जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने तथा बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने सभी नागरिकों से अधिकाधिक वृक्षारोपण करने तथा उनकी देखभाल सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

सभा को संबोधित करते हुए दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल ने कहा कि विश्वविद्यालय का स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज तथा डॉ. नित्यानंद हिमालयन शोध एवं अध्ययन केंद्र पर्यावरणीय विषयों पर गंभीर शोध एवं समाजोपयोगी शोध कार्य संचालित कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग, हिमालयी पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय चुनौतियों से जुड़े विषयों पर

विश्वविद्यालय के विद्यार्थी एवं शिक्षक निरंतर अध्ययन और अनुसंधान में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य केवल अकादमिक उत्कृष्टता तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज और मानवता के समक्ष उपस्थित चुनौतियों के समाधान में भी सक्रिय योगदान देना है। पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास से जुड़े शोध कार्य आने वाले समय में और अधिक व्यापक होंगे, जिससे समाज को व्यावहारिक एवं दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होगा।

कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. एच.सी. पुरोहित द्वारा किया गया। उन्होंने सभी अतिथियों, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों का कार्यक्रम में सहभागिता के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव दुर्गेश डिमरी, प्रो. आर.पी. मंगाई, प्रो. कुसुम अरुणाचलम्, प्रो. हर्ष डोभाल, प्रो. चेतना पोखरियाल, एस.एस. सुथार, लच्छीवाला रेंज अधिकारी सुश्री मेधावी, केदारपुरम पार्षद रोशन लाल बिंजोला, डॉ. राजेश, डॉ. विजय श्रीधर, प्रो. रीना सिंह, डॉ. विपिन सैनी, डॉ. अर्चना शर्मा, डॉ. प्राची पाठक, डॉ. चंद्रिका, डॉ. अचलेश डावरे सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी एवं पर्यावरण प्रेमी उपस्थित रहे।

हरिद्वार में चलती बस में लगी आग, चालक की सूझबूझ से यात्रियों की बची जान

पथ प्रवाह, हरिद्वार। हरिद्वार में शनिवार को सर्वानंद घाट के सामने एक बस में अचानक आग लगने से क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस और जिला प्रशासन की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। उप जिलाधिकारी हरिद्वार योगेश सिंह मेहरा ने बताया कि बस में आग लगने की सूचना प्राप्त होते ही संबंधित विभागों को सक्रिय किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर तेजी से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और कुछ ही समय में आग को पूरी तरह बुझा दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बस हरिद्वार से देहरादून की ओर जा रही थी। आग लगने के बाद चालक और परिचालक की सतर्कता से बस में सवार सभी यात्री समय रहते सुरक्षित बाहर निकल गए। प्रशासन के अनुसार घटना में किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए संबंधित विभाग द्वारा जांच की जा रही है। जिला प्रशासन ने फायर ब्रिगेड और राहत-बचाव दल की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि समय पर किए गए प्रयासों से एक बड़ा हादसा टल गया और सभी यात्रियों की जान सुरक्षित बचाई जा सकी।

विधायक आदेश चौहान ने किया काव्य संकलन मीत के अनोखे रंग का विमोचन

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

कवि अमित कुमार गुप्ता मीत के काव्य संकलन मीत के अनोखे रंग का विमोचन रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने किया। आदेश चौहान ने कहा कि साहित्यिक सृजन करने के लिये बहुत अधिक धैर्य, समर्पण व अनुभव की आवश्यकता होती है, तभी कवि ऐसी सार्थक कृति का सृजन कर पाता है, जिसे समाज भी कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता है। उन्होंने पुस्तक की एक काव्य रचना हसरतें कोशिश से पूरी होती हैं, हसरतें न हो तो जिंदगी अधूरी होती है का पाठ भी किया। साहित्यकार अरुण कुमार पाठक ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कविता हमेशा सरल, सहज व समझ में आने वाली होनी चाहिये। जिससे पाठक और श्रोता कविता स्वयं का उससे जुड़ाव महसूस कर सके।

विद्या विहार एकेडमी ज्वालापुर के सभागार में आयोजित विमोचन समारोह की अध्यक्षता डा.विजयेन्द्र पालीवाल ने और संचालन कार्यक्रम संयोजक चेतना पथ के सम्पादक

गीतकार अरुण कुमार पाठक व कवियित्री कंचन प्रभा गौतम ने किया। धन्यवाद ज्ञापन डा.ऋचा गर्ग ने किया। वयोवृद्ध कवि पं.ज्वाला प्रसाद शांडिल्य दिव्य, नवल विभा प्रकाशन से कवि शशिरंजन समदर्शी, डा.अजय पाठक, राजकुमारी राजेश्वरी, भूदत्त शर्मा, अभिनन्दन अभि रसमय, अधिवक्ता ललित मिगलानी, शान्वी, गर्वित और धान्वी, सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, पवन कुमार गर्ग, वृंदा वाणी, सुमन गुप्ता, देवेन्द्र मिश्र, सन्तोष साहू, डा.मीरा भारद्वाज, डा.नीता नय्यर निष्ठा, राकेश मालवीय, सोनेश्वर कुमार सोना, आशा साहनी, दीपक पंवार, विभा चौधरी, साधुराम पल्लव आदि ने भी कवि अमित कुमार गुप्ता को शुभकामनाएं दी। नवल विभा प्रकाशन की ओर से कवि अमित कुमार मीत को सम्मान पत्र भेंट किया गया। कार्यक्रम में नगर के अनेक साहित्यकार, कवि, लेखक तथा शिक्षाविद् शामिल रहे।

दैनिक
पथ प्रवाह
हरिद्वार, रविवार 07 जून 2026

एक नजर

इंदौर–इच्छापुर हाईवे पर जमीन निवेशकों के लिए बना सिरदर्द, करोड़ों की पूंजी फंसने का खतरा

इंदौर। मध्य प्रदेश में इंदौर-इच्छापुर हाईवे और ओंकारेश्वर से उज्जैन तक प्रस्तावित कॉरिडोर के किनारे जमीन खरीदने वाले निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। हाईवे परियोजना के शुरू होने से पहले जिन लोगों ने बड़े व्यावसायिक मुनाफे की उम्मीद में करोड़ों रुपये निवेश किए थे, अब उनके सामने निवेश डूबने का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल, राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्रवेश अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति के बनाए गए व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निरस्त किए जा सकते हैं और कार्रवाई भी हो सकती है। नियमों के अनुसार टोल प्लाजा, हाईवे कट, पुल-पुलिया, चौराहे, सर्विस रोड, हाईटेंशन लाइन और बस स्टॉप से निर्धारित दूरी बनाए रखना जरूरी है। इन्हीं नियमों के चलते बलवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों की कई जमीनें प्रभावित हो रही हैं। वहीं बलवाड़ा से ओंकारेश्वर की ओर बड़वाह बाईपास क्षेत्र में स्थित कई भूखंड हाईवे जंक्शन, सर्विस रोड और हाईटेंशन लाइन की जद में आ गए हैं। इसके अलावा प्रस्तावित आशापुर-खरगोन हाईवे के चौराहे के कारण भी अनुमति मिलने की संभावना बेहद कम बताई जा रही है। बड़वाह बाईपास स्थित एचपी पेट्रोल पंप और एसोसिएट ब्रेवरीज के आसपास खरीदी गई जमीनों पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि नियमों की अनदेखी कर जमीन खरीदने वाले निवेशकों को अब भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हाईवे किनारे निवेश से पहले कानूनी और तकनीकी नियमों की जांच जरूरी मानी जा रही है।

गाद निकासी की मांग को लेकर किसानों का अनशन जारी, प्रशासन पर वादाखिलाफी का आरोप

चेन्नई। तमिलनाडु के सत्यमंगलम क्षेत्र में नहरों और जलाशयों से गाद (सिल्ट) हटाने की मांग को लेकर किसानों का अनिश्चितकालीन अनशन लगातार जारी है। किसानों का आरोप है कि प्रशासन ने कई बार आश्वासन दिए, लेकिन अब तक गाद निकासी का काम शुरू नहीं किया गया, जिससे सिंचाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है और कृषि कार्यों पर संकट गहरा रहा है. किसानों का कहना है कि जलाशयों और नहरों में वर्षों से जमा गाद के कारण जल भंडारण क्षमता घट गई है। इससे खेतों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पा रहा है और आगामी फसलों पर भी खतरा मंडरा रहा है। आंदोलनकारी किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की यूपी पुलिस को फटकार, कहा– संविधान नहीं, सरकार के प्रति दिख रही 'वर्टिकल लॉयल्टी'

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कथित एनकाउंटर मामलों को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि पुलिस की निष्ठा संविधान और कानून के शासन के प्रति होनी चाहिए, न कि सत्तारूढ़ सरकार के प्रति। कोर्ट ने यह भी कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस बल का दायित्व निष्पक्ष रूप से कानून का पालन कराना है और वह न्यायपालिका की भूमिका नहीं निभा सकता। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कथित फर्जी मुठभेड़ों और अपराधियों को पकड़ने के नाम पर की जाने वाली कार्रवाइयों पर चिंता जताई। अदालत ने कहा कि पुलिस द्वारा किसी आरोपी को अपराधी मानकर सजा देने का अधिकार नहीं है। किसी भी व्यक्ति के दोषी या निर्दोष होने का निर्णय केवल न्यायालय कर सकता है। कोर्ट ने पहले भी उत्तर प्रदेश पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा था कि पुलिसकर्मी न्यायपालिका की भूमिका नहीं निभा सकते और मुठभेड़ों के नाम पर कानून को हाथ में लेना स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने पुलिस कार्रवाई के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए थे और कहा था कि इनके उल्लंघन को अदालत की अवमानना माना जा सकता है। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को कानून के शासन, पुलिस जवाबदेही और मानवाधिकारों के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी माना जा रहा है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अदालत का संदेश स्पष्ट है कि किसी भी लोकतंत्र में संविधान सर्वोच्च है और पुलिस की जवाबदेही उसी के प्रति होनी चाहिए, न कि किसी राजनीतिक सत्ता के प्रति।

टीएमसी में घमासान के बीच ममता बनर्जी ने संगठन में किया बड़ा फेरबदल, अभिषेक बनर्जी के पर काटे

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के भीतर जारी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने बड़ा संगठनात्मक फेरबदल किया है। पार्टी में बढ़ते असंतोष और बगावत की आशंकाओं के बीच ममता बनर्जी ने कई अहम समितियों और संगठनात्मक इकाइयों में बदलाव करते हुए अनुभवी और भरोसेमंद नेताओं को प्रमुख जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस कदम को पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करने और आंतरिक संकट से निपटने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।

रिपोर्टों के अनुसार, इस फेरबदल से ममता बनर्जी के भतीजे और पार्टी के प्रमुख नेता अभिषेक बनर्जी के प्रभाव में कमी आई है। हाल के दिनों में पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर मतभेद खुलकर सामने आए हैं और कई विधायकों तथा सांसदों के असंतोष की खबरें सामने आई हैं। ऐसे में ममता बनर्जी ने संगठन का नियंत्रण सीधे अपने हाथ में लेने की कोशिश की है। सूत्रों के मुताबिक, टीएमसी में बगावत की चर्चाओं के बीच कई नेताओं की बैठकों और संभावित टूट की अटकलों ने पार्टी नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है। हाल ही में ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई बैठक में अपेक्षा से काफी कम विधायक और सांसद पहुंचे, जिससे पार्टी के भीतर असंतोष की अटकलों को और बल मिला। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फेरबदल आगामी राजनीतिक चुनौतियों और संगठन को एकजुट रखने की दिशा में ममता बनर्जी का बड़ा दांव है। हालांकि, आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि यह कदम टीएमसी के भीतर बढ़ते असंतोष को कितना नियंत्रित कर पाता है।

सरकार का कट–ऑफ कमांड आया था : राबड़ी देवी आवास से सुरक्षा हटाने पर तेज प्रताप यादव का बड़ा आरोप

पटना। बिहार की राजनीति में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती तथा उनके पटना स्थित आवास से सुरक्षाकर्मियों को हटाए जाने पर तेज प्रताप यादव ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि सुरक्षाकर्मियों को हटाने के पीछे सरकार का कट-ऑफ कमांड था और यह कार्रवाई राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि राबड़ी देवी के आवास से सुरक्षा कर्मियों को अचानक हटाया गया, जिससे परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह फैसला केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक उद्देश्य से लिया गया है।

जीबी. पंत संस्थान ने सतत आजीविका तकनीकें, सीएम धामी ने किया स्टॉल का निरीक्षण

पथ प्रवाह, अल्मोड़ा। जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, कोसी-कटारमल ने हवालबाग में कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित 'खेत बचाओ अभियान-2026' में सक्रिय सहभागिता की। संस्थान ने प्रदर्शनी स्टॉल में सतत आजीविका व प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़ी तकनीकें प्रदर्शित कीं। इसमें पुष्पोत्पादन, चीड़ की पिरुल से बने बायो-ब्रिकेट्स, हस्तनिर्मित कागज तथा कृषि व गैर-कृषि आधारित आजीविका नवाचार शामिल रहे। किसानों और आगंतुकों ने इन्हें विशेष रुचि से देखा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संस्थान के स्टॉल का अवलोकन किया। निदेशक डॉ. आई. डी. भट्ट ने सीएम को उत्तराखण्ड में संस्थान द्वारा चलाए जा रहे जल संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, आजीविका संवर्धन और जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण से जुड़ी पहलों की जानकारी दी। स्टॉल पर बड़ी संख्या में किसानों, कृषि विशेषज्ञों व हितधारकों ने भ्रमण किया। संस्थान के वैज्ञानिक डॉ. शैलजा पुनेठा, डॉ. ललित गिरी, डॉ. डी.एस. चौहान तथा तकनीकी अधिकारी दरबान सिंह बिष्ट ने किसानों से संवाद कर पर्यावरण-अनुकूल व आजीविका उन्मुख तकनीकें अपनाने के लिए प्रेरित किया। किसानों को सतत कृषि व आजीविका विकल्पों की जानकारी भी दी गई।

पत्नी की हत्या के आरोपी पति को 24 घण्टे में किया गिरफ्तार

पथ प्रवाह, सल्ट (अल्मोड़ा)

जनपद के दूरस्थ ब्लाक अंतर्गत खुमाड़ में पत्नी की हत्या आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पति ने गुरूवार रात पत्नी की पीटकर हत्या कर दी थी। शुक्रवार को मामले को लेकर विवाहिता के भाई रजत चंद्रा निवासी रामनगर ने थाना सल्ट में तहरीर दी कि उसकी बहन भूमिका उर्फ पूजा का विवाह नवम्बर 2022में दीपक चंद्र खर्कवाल पुत्र प्रकाश चंद्र निवासी खुमाड़ (सल्ट) से हुआ था।लेकिन दीपक उसकी बहन के साथ मारपीट, उत्पीड़न कर रकम व दहेज की मॉग करता था।बीते 4जून 2026को भी उसने मेरी बहन के साथ मारपीट कर हत्या कर दी है। पुलिस ने प्राप्त तहरीर के आधार पर मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना सल्ट में एफआईआर नंबर 13/2026 धारा 80(02) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रारम्भ की।घटना की संवेदनशीलता एवं गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा चन्द्रशेखर घोडके ने तत्काल सीओ अल्मोड़ा बलवन्त सिंह रावत को घटनास्थल का निरीक्षण करने हेतु भेजा गया। साथ ही फॉरेंसिक टीम को मौके पर भेजकर घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किए गए।साथ ही प्रकरण के शीघ्र एवं निष्पक्ष अनावरण तथा आरोपी की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिसअधीक्षक हरबंस सिंह के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष सल्ट कश्मीर सिंह के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम गठित की गई।गठित पुलिस टीम ने सुरागरसी-पतारसी एवं साक्ष्यों के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दीपक चंद्र खर्कवाल उम्र-30 वर्ष पुत्र प्रकाश चन्द्र निवासी ग्राम- खुमाड़ को 24 घण्टे के भीतर कूपी बैंड सल्ट से गिरफ्तार करते हुए पंजीकृत अभियोग में आवश्यक कार्यवाही की।पुलिस टीम में थानाध्यक्ष कश्मीर सिंह, अपर उपनिरीक्षक लोमेश कुमार, कास्टेबल टोनेश त्यागी आदि शामिल हैं।

जिला परियोजना प्रबंधक ने आजीविका कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण

पथ प्रवाह, अल्मोड़ा

ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना के जिला परियोजना प्रबंधक हरीश चन्द्र तिवारी ने भिकियासैण विकासखंड का सघन दौरा कर क्षेत्र में संचालित विभिन्न आजीविका गतिविधियों और विकास कार्यों का जायजा लिया। तथा ब्लाक कार्यालय में समीक्षा बैठक की।

जिला परियोजना प्रबंधक ने संचालित पंचवाटीका, नई दिशा, जय नागार्जुन और मॉ नैथना आजीविका स्वायत्त सहकारिता के कार्यालयों का निरीक्षण किया।तथा सहकारिता के बिजनेस प्रमोटर्स के साथ बैठक कर आगामी व्यावसायिक कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि क्षेत्र में गठित सभी स्वयं सहायता समूहों की आजीविका को बढ़ाने के लिए ठोस और परिणामोन्मुखी प्रयास किए जाएं। साथ ही रीप परियोजना के तहत संचालित विभिन्न आजीविका केंद्रों का भी स्थलीय निरीक्षण किया जिसमें ?मसाला यूनिट व ड्रैगन फ्रूट उत्पादों की गुणवत्ता और बाजार लिंकेज को बेहतर करने के देते हुये स्थानीय स्तर पर पारंपरिक अनाजों के बीज उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। अल्ट्रा पूअर एंटरप्राइज (अति निर्धन उद्यम)ः नये उद्यमों का निरीक्षण कर लाभार्थियों को आवश्यक सहयोग देने की बात कही।इस मौके पर सहायक प्रबंधक रीप गोपाल चबड़ाल, सहायक प्रबंधक सुनील जोशी, खण्ड विकास अधिकारी गोपाललिंह नेगी, सहायक खण्डविकास अधिकारी सतीश पाण्डेय, मुल्याकन अनुश्रवण बृजेश गहतोड़ी, आजीविका समन्वयक दीपक शर्मा, ब्लाक मिशन प्रबंधक चन्द्र किशोर, उमेश रावत, अशोक कठायात, भारत बिष्ट, अनीता रावत, पंकज मठपाल.महेश बसेड़ा, सुरेश न, संजय रीना, राजेंद्र, दिनेश आदि मौजूद रहे।

सिविल अस्पताल की बड़ी उपलब्धि : दुर्लभ जटिल सर्जरी से बालक को मिला सामान्य जीवन

अहमदाबाद। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन तथा स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रफुल पानशेरिया के नेतृत्व में गुजरात सरकार की प्रजानोन्मुखी स्वास्थ्य नीति और सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाओं का एक उत्कृष्ट उदाहरण एक बार फिर अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में देखने को मिला है। सिविल अस्पताल के बाल रोग (पीडियाट्रिक सर्जरी) विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने एक अत्यंत जटिल और दुर्लभ सर्जरी कर उत्तर प्रदेश के एक साधारण किसान परिवार के 12 वर्षीय बालक को नया जीवन दिया है। मात्र 25 दिन की नवजात अवस्था की उम्र में कुत्ते के हमले का शिकार बने इस बच्चे के जननांग का 12 वर्ष बाद सफल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी द्वारा फिर से सामान्य किया गया।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रफुल पानशेरिया ने भी इस अनूठी उपलब्धि के लिए सिविल की पूरी मेडिकल टीम को बधाई देते हुए कहा कि गुजरात सरकार के आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के कारण ही आज देश और दुनिया भर के मरीजों को ऐसी जटिल चिकित्सा सेवाएं पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध हो रही हैं।

उत्तर प्रदेश के आगरा निवासी सुरेश यादव का पुत्र जब मात्र 25 दिन का था, तब एक कुत्ते ने उस पर हमला कर उसके बाह्य जननांग को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था। जैसे-जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती गई, उसकी परेशानियां भी असहनीय होती गईं। बच्चे को पेशाब करने में अत्यंत कठिनाई होती थी और उसके जननांग का विकास पूरी तरह रुक गया था। कई स्थानों पर उपचार कराने के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। अंततः यह परिवार उम्मीद लेकर अहमदाबाद सिविल अस्पताल पहुंचा।

बच्चे को 1 मई, 2026 को भर्ती किए जाने के बाद सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक एवं बाल रोग सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉ. राकेश जोशी ने जांच की। जांच में पता चला कि बच्चे के दोनों वृषण (टेस्टिस) अनुपस्थित थे, लिंग अंदर की ओर दब गया था तथा मूत्रमार्ग का छिद्र अत्यंत संकरा हो गया था।

एक नजर

शहर के विकास की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

पथ प्रवाह, हरिद्वार। राज्य आंदोलनकारी एवं भाजपा कार्यकर्ता चौगेशचंद्र पांडे तथा स्वामी रामप्रकाश चैरिटेबल हॉस्पिटल के निदेशक डा.संजय शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन प्रेषित कर कुंभ क्षेत्र और शहर के विकास से संबंधित कई जनहितकारी प्रस्तावों पर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में चौगेशचंद्र पांडे एवं डा.संजय शाह ने कहा कि हरिद्वार में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिसके चलते यातायात, पार्किंग, सुरक्षा और सौंदर्यीकरण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कुंभ क्षेत्र में निर्माणाधीन फ्लाईओवर मिट्टी आधारित न होकर आरसीसी संरचना में बनाए जाएं, ताकि उनके नीचे पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था विकसित की जा सके। ऋषिकुल पुल और शंकराचार्य चौक पर यातायात के भारी दबाव को देखते हुए फ्लाईओवर निर्माण किया जाए। इसके अलावा प्रेमनगर पुल से कृष्णा नगर पुलिया तक फ्लाईओवर अथवा उच्च स्तरीय सड़क मार्ग का निर्माण तथा रामदेव की पुलिया क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण या फ्लाईओवर का निर्माण किया जाए। जिससे शहर के भीतर यातायात का दबाव कम हो सके। ज्ञापन में चैगेशचंद्र पांडे एवं डा. संजय शाह ने घाटों के विकास को लेकर भी कई सुझाव दिए गए हैं। जिसमें नए घाटों पर सीढ़ियां नदी की तलहटी तक बनाने, ताकि जलस्तर कम होने की स्थिति में श्रद्धालुओं को सुरक्षा दीवार पार कर नीचे न उतरना पड़े और दुर्घटनाओं की संभावना कम हो। इसके साथ ही नव निर्मित और प्रस्तावित घाटों पर पर्याप्त हाई मास्ट लाइट एवं एलईडी प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई है। ज्ञापन में नए हरिद्वार गंगा पुल के शीघ्र विस्तार, प्रस्तावित रिंग रोड से जुड़ी सड़कों का 30 से 40 फीट तक चौड़ीकरण, ऋषिकुल तिराहे से ऋषिकुल पुल तक सड़क चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण तथा ऋषिकुल मैदान में बाउंड्री वॉल निर्माण करने की मांग भी की गई है। इसके अलावा श्रीयंत्र मंदिर पुल से बैरागी कैंप रोड तक स्थित छोटे सड़क मार्ग के निर्माण और सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव भी रखा गया है, जिससे स्थानीय नागरिकों, श्रद्धालुओं और वाहनों की आवाजाही अधिक सुगम और सुरक्षित हो सके।

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस पर किया यज्ञ और जलाभिषेक

पथ प्रवाह, हरिद्वार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस के अवसर पर विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने लकसर स्थित पार्थेश्वर महादेव मंदिर में यज्ञ और जलाभिषेक किया और उनके प्रधानमंत्री बनने की कामना की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर स्वामी राम मुनि महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति अपने मूल स्वरूप में लौट रहे हैं। न्याय और सुशासन से राम राज्य जैसी अनुभूति हो रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। समस्त सन्त समाज चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ देश का नेतृत्व करें। इस अवसर पर मंदिर के संचालक अखिल गिरी महाराज, विश्व हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सचिव कुलदीप सैनी, प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भूषण, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अजय वर्मा, नरेश भगत बर्फानी, प्रदेश महामंत्री अर्जुन शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप शर्मा, प्रदेश सचिव सोनू कश्यप, जिला अध्यक्ष संदीप प्रजापति, जिला महामंत्री चंद्रप्रकाश वाल्मीकि, जिला महामंत्री विकास भाटी, जिला उपाध्यक्ष अंजनेश कश्यप, जिला उपाध्यक्ष सतीश चौधरी, जिला उपाध्यक्ष पवन कश्यप, विधानसभा अध्यक्ष सागर आदि सैंकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध

पथ प्रवाह, हरिद्वार। जगजीतपुर के वार्ड 57 में पुलिस बल के साथ स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची ऊर्जा विभाग की टीम का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव वरूण बालियान ने आरोप लगाया कि स्थानीय लोगों के मीटर बदलने से इंकार करने पर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने विद्युत कनेक्शन काट दिए। वरूण बालियान ने आरोप लगाया कि एक प्राइवेट कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार जबरन स्मार्ट मीटर लगवाकर लोगों को लूटने का काम कर रही है। लोगों को एकजुट होकर सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ खड़ा होना होगा। वरूण बालियान ने कहा कि लोगों की सहमति के बिना ही ठीक काम कर रहे पुराने मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। जिसे सहन नहीं किया जाएगा। विरोध करने वालों में प्रदीप कुमार, कमल राजपूत, अनिल सैनी, आकाश वालिया, देवेश बर्मन, महेश बर्मन, विनोद नौटियाल, सुनील चौधरी, गीता, शांति देवी, रेखा आदि शामिल रहे।

कुंभ मेला प्रशासन ने अभी तक नहीं ली अखाड़ों की सुध- महंत जसविंदर सिंह

पथ प्रवाह, हरिद्वार। अगले वर्ष होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर कनखल स्थित श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल में संतों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए अखाड़े के कोठारी महंत जसविंदर सिंह महाराज ने कहा कि कुंभ मेला शुरू होने में केवल 6 महीने का समय शेष बचा है। लेकिन सरकार और कुंभ मेला प्रशासन ने अभी तक अखाड़ों की कोई सुध नहीं ली है। कोठारी महंत जसविंदर सिंह महाराज ने कहा कि नासिक कुंभ मेले को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने अधिकारियों को तत्परता से सभी कार्य समय पर पूरे करने और अखाड़ों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले के दौरान अखाड़ों को धर्मध्वजा की स्थापना, पेशवाई तथा बाहर से आने वाले संतों और श्रद्धालुओं के आवास आदि सहित अनेक व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। जिसके लिए अखाड़ों और मेला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता होती है। हरिद्वार कुंभ मेला प्रशासन द्वारा अखाड़ों की सुध नहीं लिए जाने से अखाड़ों के स्तर पर होने वाली तैयारियां प्रभावित होंगी। इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कुंभ मेला प्रशासन को अखाड़ों से समन्वय स्थापित करने के संबंध में निर्देश जारी करने चाहिए। जिससे सभी तैयारियां समय से पूरी हो सकें। बैठक में महंत खेमसिंह, महंत निर्भय सिंह, महंत अंग्रेज सिंह, संत बीर सिंह, महंत जसकरण सिंह, डा.स्वामी केशवानंद, महंत गुरप्रीत सिंह, महंत सुखमन सिंह, महंत जसकरण सिंह, संत विष्णु सिंह आदि संत मौजूद रहे।

नितिन गौतम ने दर्जा मंत्री बनने पर किया गंगा पूजन

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

उत्तराखंड सरकार में दर्जा राज्यमंत्री (ग्रामीण स्वास्थ सलाहकार एवम् अनुश्रवण परिषद उपाध्यक्ष)बनने पर भाजपा नेता नितिन गौतम ने हरकी पौड़ी पहुँच कर गंगा पूजन कर माँ गंगा का आशीर्वाद लिया।

गंगा पूजन कर राज्यमंत्री नितिन गौतम ने कहा कि भाजपा सरकार और संगठन ने जिस विश्वास के साथ ये जिम्मेदारी मुझको दी है मैं पूरी निष्ठा और लगन से इसका निर्वाह करुगा और सरकार की जनकल्याण की योजनाओं को जन जन तक पहुचाने का कार्य करुगा। उन्होंने कहा की भाजपा ही एक मात्र ऐसी पार्टी है जो अपने सभी कार्यकर्ताओ को समय समय पर जिम्मेदारी प्रदान करती है। गौतम ने कहा की मैं अपने दायित्व को जनता और सरकार के बीच का सेतु बनाने का करूँ करुगा, आज देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निरन्तर विकास की गंगा देश व प्रदेश मे बहा रहे है। आज स्नातन संस्कृति को सुरक्षित करने का कार्य देश में हो रहा है और भारत पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। गौतम ने कहा की कार्यकर्ता अपने मन से देश और संगठन की सेवा करता रहे पार्टी एक दिन उस पर विचार अवश्य करती है।

इस अवसर पर स्वामी ऋषिश्रवानंद व जिला महामंत्री भाजपा संजीव चौधरी ने कहा कि भाजपा अपने कार्यकर्ता को समय समय पर सम्मान देती आई है। नितिन गौतम अपने बाल्य काल से ही संगठन के सच्चे सिपाही के रूप में कार्य करते आ रहे है। विहिप के जिला अध्यक्ष से लेकर अनेक दायित्व का सफलता से निर्वहन गौतम ने किया है। साथ ही धर्म के हितों के लिए हुए बड़े बड़े आंदोलन में अग्रणी भूमिका में रहे है। आज एक समय कार्यकर्ता से और राज्यमंत्री बनने के पीछे उनकी निष्ठा और देश प्रेम है।

इस अवसर पर गंगा सभा महामंत्री तन्मय वशिष्ठ, सभापति कृष्णकुमार, ठेकेदार योगी, आशुतोष जिला उपाध्यक्ष, आशु चौधरी जिला मंत्री, विनीत जॉली, पूर्व जिला अध्यक्ष संदीप गोयल, वरिष्ठ नेता उज्जवल पंडित, सिद्धार्थ चक्रपाणि, आशीष मारवाड़ी, मंडल अध्यक्ष वरुण वशिष्ठ आदि भाजपा व गंगा सभा पदाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे।

तेल कंपनियों का घाटा नहीं हो रहा कम... आम आदमी की जेब पर फिर गिरेगी गाज

5 रूपए तक महंगा हो सकता है पेट्रोल-डीजल !

नई दिल्ली। मई महीने के दूसरे हाफ में पेट्रोल और डीजल की कीमत में करीब 8 फीसदी का इजाफा होने के बाद और इजाफा देखने को मिल सकता है। जानकारी के अनुसार फ्यूल की कीमतों में और 5 रुपए प्रति लीटर की तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों को कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और पश्चिम एशिया संकट के कारण फ्यूल से होने वाले नुकसान की वजह से हर दिन लगभग 610 करोड़ का घाटा (अंडर-रिकवरी) हो रहा है। 15 मई से पेट्रोल और डीजल की रिटेल कीमतों में कुल मिलाकर लगभग 7.5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बावजूद, तेल कंपनियों को अभी भी पेट्रोल पर लगभग 5.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 4.5 रुपए प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है। तीनों सरकारी फ्यूल कंपनियों को मिलाकर कुल मिलाकर हर दिन लगभग 610 करोड़ रुपए का घाटा हो सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 5 प्रति लीटर की और बढ़ोतरी से कंपनियों को ऑटो फ्यूल की बिक्री पर 'ब्रेक-ईवन' (यानी लागत और कमाई बराबर होने) की स्थिति के करीब पहुंचने में मदद मिल सकती है।

यह नुकसान सिर्फ ऑटो फ्यूल तक ही सीमित नहीं है। आईसीआरए का अनुमान है कि आईएलपजी पर घाटा (अंडर-रिकवरी) लगभग 680 रुपए प्रति सिलेंडर बना हुआ है, जबकि एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर नुकसान लगभग 93 करोड़ रुपए प्रतिदिन है। क्रिसिल रेटिंग्स के विश्लेषण के अनुसार, अगर कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं और तेल कंपनियां अपना घाटा कम करना जारी रखती हैं, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुल बढ़ोतरी 10 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच सकती है।

इकोनॉमी पर पड़ेगा असर

क्रिसिल ने कहा कि इसका व्यापक असर पूरी इकोनॉमी पर पड़ेगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ेगी, जिससे खाने-पीने की चीजों और कोर महंगाई, दोनों में बढ़ोतरी होगी। रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 7.5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी से कंज्यूमर महंगाई में लगभग 36 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि कुल 10 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी से यह असर 48 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ सकता है। माना जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट की लागत ही महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण होगी। क्रिसिल ने बताया कि भारत की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में माल ढुलाई का हिस्सा 54 फीसदी है, जबकि सड़क परिवहन से कुल माल ढुलाई का लगभग 71 फीसदी हिस्सा ढोया जाता है। सड़क परिवहन की लागत में अकेले ईंधन का हिस्सा लगभग 42 फीसदी है, जिससे ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से सप्लाई चेन पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। नतीजतन, ट्रांसपोर्ट पर निर्भर सेक्टरों को ज्यादा कॉस्ट का सामना करना पड़ सकता है। क्रिसिल का कहना है कि डेयरी प्रोडक्ट्स, फल, दालें, मसाले, चाय, कॉफी, अंडे, मीट और मछली जैसी चीजों की कीमतों में ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ने से रिटेल कीमतें भी बढ़ रही हैं।

एक नजर

माटी कला बोर्ड के सदस्य बनाए गए श्यामल कुमार ने जताया आभार

पथ प्रवाह, हरिद्वार। वरिष्ठ भाजपा नेता श्यामल कुमार को माटी कला बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया गया है। माटी कला बोर्ड में सदस्य पद की जिम्मेदारी दिए जाने पर श्यामल कुमार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, पार्टी नेतृत्व, समस्त संगठन तथा कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया है। आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा एक साधारण कार्यकर्ता को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपना उनके लिए गौरव, सम्मान और प्रेरणा का विषय है। यह दायित्व केवल एक पद नहीं, बल्कि जनसेवा और संगठन के प्रति जवाबदेही को और अधिक बढ़ाने वाला अवसर है। उन्होंने कहा कि पार्टी की नीतियों, संगठन के मूल्यों तथा उत्तराखंड के जनहित को सर्वोपरि रखते हुए पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

राम कथा के श्रवण से कल्याण और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है-स्वामी राजराजेश्वराश्रम

पथ प्रवाह, हरिद्वार। जगदुरू शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम महाराज ने कहा कि भगवान श्रीराम जन-जन के आराध्य हैं। मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्रीराम की कथा का श्रवण करने से कल्याण और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज के संयोजन मे श्री दक्षिण काली मंदिर में आयोजित श्रीराम कथा के शुभारंभ अवसर पर श्रद्धालु भक्तों को संबोधित करते हुए स्वामी राजराजेश्वराश्रम महाराज ने कहा कि मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्रीराम का जीवन हमें मर्यादा, त्याग और ईश्वर भक्ति का मार्ग दिखाता है। जिससे धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि कलियुग में राम नाम का स्मरण ही मुक्ति का माध्यम है। राम नाम की महिमा इतनी अपरंपार है कि राम नाम स्मरण करने मात्र से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि श्रीराम कथा का श्रवण करने के साथ कथा से मिले ज्ञान को आचरण में धारण कर आदर्श समाज बनाने में सहयोग करें। श्रद्धालुओं को कथा श्रवण कराते हुए स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने कहा कि भगवान श्रीराम की शरण में जाने से व्यक्ति का जीवन भवसागर से पार होता है। रामकथा सुनने मात्र से जीवन के सभी कष्ट और संशय दूर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि हर परिस्थिति में धर्म का पालन करने वाले प्रभु श्रीराम के प्रति पूर्ण समर्पण से ही वास्तविक आनंद की प्राप्ति होती है। स्वामी कैलाशानंद गिरी के शिष्य स्वामी अवंतिकानंद ब्रह्मचारी ने बताया कि 14 जून तक चलने वाली श्रीराम कथा में देश विदेश के श्रद्धालु शामिल होंगे। उन्होंने सभी से कथा श्रवण का लाभ उठाने की अपील भी की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त मौजूद रहे।

आत्माराम बेनीवाल अध्यक्ष, नीरज छाछर बने महामंत्री

पथ प्रवाह, हरिद्वार। कनखल वाल्मीकि समाज पंचायत कमेटी का पुर्नगठन किया गया है। आत्माराम बेनीवाल पुनः कमेटी के अध्यक्ष, नीरज छाछर महामंत्री व अशोक वैद कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। वाल्मीकि आश्रम कनखल में आयोजित समाज की बैठक में समाज के वरिष्ठ लोगों द्वारा बीते तीन साल पहले चुनी हुई कमेटी के कार्यों को देखते हुए वाल्मीकि समाज पंचायत कमेटी का पुनर्गठन किए जाने का निर्णय लेते हुए आत्माराम बेनीवाल अध्यक्ष, अशोक तेश्वर कार्यवाहक अध्यक्ष, नाथीराम पेवल उपाध्यक्ष, नीरज छाछर महामंत्री, अशोक वैद कोषाध्यक्ष, बलराम चैटाला संगठन मंत्री, उमेश धीलौड़ को प्रचार मंत्री नियुक्त किया गया। घनश्याम पेवल, अजय वैद, मुकेश तेश्वर, सावन वैद, विपिन पेवल, दिनेश तेश्वर, विनोद चावला, अनुरोध चंचल को व्यवस्थापक कमेटी में शामिल किया गया है। बैठक के दौरान समाज के वरिष्ठजनों को शामिल करते हुए मार्गदर्शक मंडल का भी गठन किया गया। जिसमें चौ.सुरेंद्र तेश्वर, डालचंद छाछर, ओम प्रकाश तेश्वर, रामदर्शन छाछर, भभूतिराम तेश्वर, जयपाल सिंह, ओमदत्त बेनीवाल, हरबंश चंचल, शिवप्रसाद छाछर, चंद्रभान आदि शामिल हैं। बैठक की अध्यक्षता करते हुए चै.सुरेंद्र तेश्वर ने कमेटी के सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि कमेटी ने अपने पिछले कार्यकाल में समाज हित एवं जनहित में जो कार्य किए हैं वह सराहनीय हैं। इनकी इस पहल से समाज निश्चित रूप से एक नई दिशा में जाने की तैयारी कर रहा है। वाल्मीकि आश्रम के पीठाधीश्वर श्रीमहंत मानदास महाराज ने सभी पदाधिकारियों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि कमेटी ने अपने पिछले कार्यकाल में समाज हित में जो कार्य किए हैं। उनसे समाज में फैली अव्यवस्था व कुरीतियां काफी हद तक दूर हुई है। इसके लिए कमेटी के सभी पदाधिकारी व सदस्य बधाई के पात्र हैं।

ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एनआरआई की हत्या का खुलासा, संपत्ति के लिए भाई ने किया कत्ल

अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एनआरआई सुनील शर्मा की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया है कि सुनील शर्मा की हत्या उनके सगे भाई सतीश शर्मा ने करोड़ों रुपये की संपत्ति हड़पने के लिए रची गई साजिश के तहत करवाई थी। अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

अमृतसर ग्रामीण के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कंवलप्रीत सिंह चहल के अनुसार, 23 मई को सुनील शर्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जांच शुरू की गई। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन डेटा और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। जांच में पता चला कि सतीश शर्मा ने अपने बेटे सनी शर्मा और प्रॉपर्टी डीलर लखविंदर सिंह के साथ मिलकर सुनील शर्मा को संपत्ति के सौदे के बहाने बुलाया। आरोप है कि उन्हें नींद की गोलियां देकर बेहोश किया गया और बाद में सिर पर वार कर उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए खून से सने बिस्तर और अन्य सामग्री को छिपाने की कोशिश की गई। पुलिस के मुताबिक, सुनील शर्मा पंजाब में लगभग पांच से छह करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों के मालिक थे।

पौड़ी जनपद को शीघ्र मिलेगी आधुनिक इंडोर खेल सुविधा, जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण

पथ प्रवाह, पौड़ी।

जनपद मुख्यालय स्थित कण्डोलिया इंडोर स्टेडियम को आधुनिक खेल सुविधाओं से युक्त विकसित खेल परिसर के रूप में तैयार करने की दिशा में कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने शनिवार को इण्डोर स्टेडियम एवं खेल कार्यालय का निरीक्षण कर चल रहे विकास कार्यों, उपलब्ध खेल सुविधाओं तथा आधारभूत व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में किए गए निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों के क्रम में बैडमिंटन कोर्ट के सुदृढ़ीकरण हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी थी, जिसके उपरांत लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य प्रारंभ कराया गया। लंबे समय से उपयोग के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी फ्लोरिंग को बदलते हुए कोर्ट का पुनर्निर्माण कराया गया है। इसके अंतर्गत आधुनिक फ्लोरिंग और कोर्ट मैट स्थापित किए गए हैं, जिससे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बेहतर खेल वातावरण प्राप्त होगा। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के खिलाड़ियों को बेहतर खेल अवसर उपलब्ध कराने के लिए खेल अवसंरचना को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इण्डोर स्टेडियम में चार बैडमिंटन कोर्ट बनाए जा रहे हैं, जिनके सुदृढ़ीकरण का कार्य लगभग पूर्णता की ओर है तथा शीघ्र ही खिलाड़ियों को आधुनिक, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण इण्डोर खेल सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। जिलाधिकारी ने स्टेडियम में हाल ही में स्थापित प्रकाश व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए आवश्यक स्थानों पर अतिरिक्त लाइटें लगाने, मुख्य प्रवेश द्वार पर फोकस लाइट स्थापित करने तथा आकर्षक साइनेज बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खेल सुविधाओं के साथ-साथ परिसर का समुचित सौंदर्यीकरण भी आवश्यक है, जिससे खिलाड़ियों और आगंतुकों को बेहतर अनुभव प्राप्त हो। स्टेडियम परिसर को अधिक सुव्यवस्थित एवं आकर्षक बनाने के लिए उन्होंने पाइपलाइन व्यवस्था को व्यवस्थित करने, जालियों पर रंग-रोगन कराने तथा भवन के रखरखाव कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। लकड़ी से निर्मित संरचनाओं के संरक्षण हेतु गुणवत्तापूर्ण वुडन पॉलिश कराने को भी कहा गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने उपकरणों एवं खेल सामग्री के सुरक्षित रखरखाव के लिए कैबिनेट निर्माण, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था तथा नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने खेल कार्यालय में पेयजल एवं शौचालय सुविधाओं की भी समीक्षा की और खिलाड़ियों के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं बेहतर बनाए रखने पर जोर दिया। लॉन टेनिस कोर्ट के आसपास आवश्यक विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों के लिए विस्तृत आकलन तैयार करने के निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने जलापूर्ति व्यवस्था की भी जांच कराने को कहा। उन्होंने सभी जल कनेक्शनों को सुचारु रखने तथा खेल परिसरों के रखरखाव को नियमित रूप से मॉनिटर करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि आधुनिक खेल अवसंरचना का विकास केवल खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जनपद में खेल संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निरीक्षण के दौरान दिए गए सभी निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान जिला क्रीड़ा अधिकारी जयबीर रावत, डीएसटीओ राम सलोने, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग विवेक सेमवाल, कनिष्ठ अभियंता वैभव चन्दोला सहित अन्य अधिकारी एवं कोच उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन, पंचायतों को अधिक अधिकार और संसाधन देने की मांग

पथ प्रवाह, अल्मोड़ा।

ग्राम प्रधान संगठन, विकासखंड हवालबाग ने पंचायतों और ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। अल्मोड़ा में आयोजित खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि पंचायत चुनाव संपन्न हुए लगभग दस माह बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उप-प्रधानों का चुनाव नहीं हो पाया है। संगठन के अनुसार उप-प्रधानों के निर्वाचन के अभाव में पंचायतें पूर्ण रूप से कार्यशील नहीं हो पा रही हैं। इसलिए उप-प्रधानों के चुनाव शीघ्र कराए जाने की मांग की गई है। ग्राम प्रधान संगठन ने राज्य वित्त से मिलने वाली धनराशि में कंटिजेंसी मद की कटौती पर भी आपत्ति जताई। संगठन का कहना है कि इसी राशि से प्रधानों और उप-प्रधानों के मानदेय का भुगतान किया जा रहा है, जिससे पंचायतों के नियमित कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ज्ञापन में पंचायत निधियों पर प्राप्त ब्याज के उपयोग का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिए जाने तथा मानदेय की अलग व्यवस्था किए जाने की मांग उठाई गई। संगठन ने ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ाकर न्यूनतम 15 हजार रुपये प्रतिमाह करने की भी मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि ग्राम प्रधान विकास कार्यों के संचालन, जनसमस्याओं के समाधान, आपदा प्रबंधन और प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन में लगातार सक्रिय रहते हैं, जबकि वर्तमान मानदेय उनकी जिम्मेदारियों के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा वीबी-जीरामजी योजना की गाइडलाइन को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित करने की मांग की गई है। संगठन का कहना है कि वर्तमान मानक पहाड़ी क्षेत्रों की आवश्यकताओं से मेल नहीं खाते, जिससे विकास कार्यों की प्रभावशीलता प्रभावित होती है। ज्ञापन में पंचायती राज अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए ग्राम पंचायतों को अधिक वित्तीय, प्रशासनिक और विकासात्मक अधिकार दिए जाने की भी मांग की गई। संगठन ने उम्मीद जताई कि सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेकर पंचायत व्यवस्था को अधिक सशक्त बनाने की दिशा में कदम उठाएगी।

यहाँ ज्ञापन देने वालों में संगठन अध्यक्ष देवेंद्र सिंह नयाल, महामंत्री विनोद जोशी, उपाध्यक्ष सुंदर मटियानी, चंद्रिका तिवारी, देवेंद्र मेहरा आदि मौजूद रहे।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाया सवाल, की सख्त टिप्पणी

अधिकारियों की वफादारी संविधान नहीं, सत्ताधारी दल के प्रति

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी संविधान के बजाय सत्ताधारी सरकार के प्रति ज़्यादा वफादार हैं। यूपी पुलिस के कामकाज की कड़ी आलोचना करते हुए जस्टिस विनोद दिवाकर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में नेताओं और नौकरशाहों की सामंती सोच ने लंबे समय से संवैधानिक शासन को जनसेवा के बजाय निजी प्रभुत्व का जरिया बना दिया है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने कहा, राज्य की प्रशासनिक मशीनरी गहरी राजनीतिक पैठ के प्रति संवेदनशील रही है। इसमें कहा गया है कि यूपी में अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और पदोन्नति योग्यता-आधारित शासन के बजाय राजनीतिक संरक्षण के साधन हैं। बेंच ने कहा कि वफादार माने जाने वाले अधिकारियों को पसंदीदा पोस्टिंग-अर्बन कमिश्नरेट, आकर्षक जिले से पुरस्कृत किया जाता है, जबकि स्वतंत्रता का प्रदर्शन करने वालों को दंडात्मक रूप से महत्वहीन कार्यों में स्थानांतरित कर दिया जाता है, यह एक सर्वविदित तथ्य है।

अधिकारियों की वफादारी सत्ताधारी व्यवस्था के प्रति होती है

कोर्ट ने आगे कहा कि अधिकारियों की वफादारी संविधान के प्रति नहीं, बल्कि सत्ताधारी व्यवस्था के प्रति होती है। फील्ड अधिकारी, जो ट्रांसफर-पोस्टिंग के खेल को अच्छी तरह समझते हैं, अपने व्यवहार को राजनीतिक आकाओं को खुश करने के हिसाब से ढालते हैं। एनकाउंटर में हत्याएं, चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई और परेशान करने वाले लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का इस्तेमाल जैसे मामलों पर समय-समय पर अदालतों का ध्यान गया है। उत्तर प्रदेश में पुलिस के कामकाज और कानून के शासन पर कड़ी टिप्पणी करते हुए जस्टिस दिवाकर ने कहा कि अधिकारियों का एक बड़ा वर्ग कानून के शासन को संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि काम-काज में आने वाली एक रुकावट मानता है। बिना सही प्रक्रिया के गिरफ्तारियां की जाती हैं, कई बार गलत इरादों से एफआईआर दर्ज की जाती हैं या दबा दी जाती हैं और अधिकारियों की मनमर्जी से एहतियातन हिरासत के प्रावधानों का मनमाना इस्तेमाल किया जाता है। बेंच ने आगे कहा कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (और अब 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता') के तहत मिलने वाली प्रक्रियात्मक सुरक्षा को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।

स्वामी/प्रकाशक वीरेन्द्र सिंह ने मुद्रक प्रमोद कुमार, जय माँ गंगा प्रिन्टर्स, राजराणा कॉम्पलैक्स निकट खाद गोदाम, जमालपुर कलां, ज्वालापुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) से मुद्रित कराकर, मुख्य कार्यालयः 40 शांतिपुरम कॉलोनी जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार, उत्तराखंड 249408 (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित किया। वीरेन्द्र सिंह (सम्पादक) 9411111733, डॉ सुशील शर्मा(उप संपादक) 9837906777 किसी भी वाद विवाद का निपटारा हरिद्वार में होगा। वेबसाईट- www.pathpravah.com